04 - वेनेजुएला के बाद क्या क्यूबा की बारी है

05 - कूदोपाली : पथरीली जमीन पर 'शिक्षा के फूल'

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 21 मई, 2026

06 - प्रधानमंत्री का संकल्प, 2047 तक कोई भी बच्चा सिकल सेल से प्रभावित...

07 - विकासखंड नटेरन की ग्राम पंचायतों में कृषकों के समक्ष...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 258, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

देशी बीमा कंपनियों पर विदेशी कब्जा और हितग्राहियों की चिंताएं

अरविंद मोहन

सोलह मई को ठीक छह महीने हुए जब सरकार ने 'सबको बीमा, सबकी रक्षा' जैसे आकर्षक नाम से बीमा व्यवसाय को शत-प्रतिशत विदेशी पूंजी के लिए खोलने का बिल पेश किया था। और इसी 16 मई को पहली बड़ी ख़बर आई कि भारतीय बीमा कंपनी भारती अक्सा ब्रिटिश कंपनी प्रूडेन्शियल के हवाले हो गई। मिल्कियत के साथ मैनेजमेंट भी उसके हाथ आ गया है। इस बदलाव की नींव पिछले साल के बजट से पड़ी थी और संसद के दोनों सदनों में भाजपा तथा एनडीए की जो स्थिति है उसमें इस बिल को पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई। और पिछली बार भारतीय मजदूर संघ समेत की मज़दूर यूनियनों और राजनैतिक दलों की तरफ से विरोध का जो स्वर सुनाई दिया था इस बार कहीं से भी चूं की आवाज भी नहीं आई।

इसे सर्वसम्मति का मामला नहीं मानना चाहिए लेकिन मोटे अर्थों में सभी दलों में इस पर सहमति है भी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से बार-बार बीमा निजीकरण का सवाल उठता रहा है और इसमें निवेश की सीमा 26 फ़ीसदी, 49 फीसदी और 75 फीसदी तक बढ़ाने के साथ प्रबंधन और मुनाफा बाहर ले जाने की इजाजत देने के सवाल भी उठते रहे हैं। हां अभी तक एक ही मामले में सहमति नहीं बनी है कि बीमा प्रीमियम के पैसे विदेश जाने की अनुमति नहीं है।

उदारीकरण की आर्थिक नीतियों पर हमारे राजनैतिक दलों में एक सर्वसम्मति सी बन गई थी और है भी। पर बीमा के सवाल पर एक झिझक सी रही है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीयकरण के पहले देश में जो निजी बीमा कंपनियां थीं, उनके काम को लेकर काफी शिकायतें थीं और उनका दायरा भी बहुत सीमित था। जब से सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद से बीमा का दायरा बढ़ा, क्लेम निपटान का रेट सुधारा, लोगों की शिकायतें कम हुईं और सबसे बढ़कर यह बात हुई कि प्रीमियम का पैसा सरकार के हाथ आया जिससे विकास की अनेक योजनाओं के लिए रेडी कैपिटल मिला।

कई बार सरकारी निर्देश से बीमा कंपनियों की पूंजी का नाश भी हुआ, लेकिन ऐसे अवसर कम आये। यूटीआई घोटाले में जरूर बीमा निगम की पूंजी के सहारे संकट निपटाया गया। और आज भी क्लेम निपटाने के मामले में हमारी पांचों सरकारी कंपनियां ही पहले पाँच पायदानों पर हैं। निजी और विदेशी कंपनियों का नंबर इनके बाद ही आता है। कहना न होगा कि विदेशी कंपनियों की मजबूत लीगल टोलियां और चंट वकील गरीब ग्राहकों का क्लेम रोकने में सफल हो जाते हैं।

और अपने यहां बीमा के नाम पर उदारीकरण वाले दौर में जो 'घोटाले' हुए हैं वह भी कई बार राजनेताओं और उनसे भी बढ़कर ट्रेड यूनियन नेताओं को इसके खिलाफ पोजीशन लेने के लिए मजबूर करते हैं। बीते काफी समय से फसल बीमा और हेल्थ बीमा की चर्चा राजनीतिक हलके में ज्यादा रही है, अंडरराइटिंग क्या बला है या बड़े सौदे कैसे होते हैं, यह तो ठीक से पता भी नहीं है। लेकिन जो फसल बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चली हैं उनका अनुभव यह रहा है कि जितनी रकम बीमा के प्रीमियम के रूप में दी जाती है उसका दस फीसदी भी भुगतान क्लेम के रूप में नहीं हुआ है। और इस प्रीमियम की वसूली भी सिर्फ एक ग्राहक-सरकार से लेनी हो तो कंपनियों की पौ बारह हो जाती है। उल्लेखनीय है कि ऐसे सारे कार्यक्रमों में निजी बीमा कंपनियों को ही ज्यादा अवसर दिया गया है। और कई बार लगता है कि यह भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय है जो उदारीकरण और बीमा निजीकरण के साथ आया है। जब बीमा कंपनी और मंत्री/सचिव में डील हो गई हो तो किसान हो या मरीज उस बेचारे की क्या औकात रह जाती है क्लेम लेने की। और जनता के कर का पैसा होने से शोर मचाने वाले भी सामने नहीं आते। अपने यहां क्लेम का मामला तब सामने आता है जब ग्राहक सीधे कंपनी को प्रीमियम देते हैं और उनको सेवा मिलने में या पॉलिसी मैच्योर होने पर पैसे वापस पाने में मुश्किल आती है। अपने यहां सबसे ज़्यादा झमेला किसी और योजना में पॉलिसी देने का वायदा करके एजेंट कंपनी की सुविधा के अनुसार दूसरी योजना में पैसे डाल देने का है। ऐसा अक्सर बाजार में निवेश के म्यूचुअल फंड के खेल में किया जाता है। और वहां जब पूंजी डूबती है तो ग्राहक का सिर कुचला जाता है। ऐसी शिकायतें आम हैं लेकिन उनका निपटारा ढंग से नहीं होता और शिकायतों का क्रम बढ़ता जा रहा है। सरकारों को बीमा व्यवसाय को विदेशी निवेश के लिए खोलने की जल्दबाजी तो रही है लेकिन ग्राहकों की शिकायत निपटाने का होश नहीं रहता। और कंपनियां किन वायदों के साथ आती हैं और उनका काम किस दिशा में जाता है यह चेक करना तो सरकार अपनी जवाबदेही मानती ही नहीं, बीमा प्रोडक्ट की वेराइटी बढ़ाना और ग्राहकों के सामने नए विकल्प आना हुआ भी है या नहीं कोई नहीं देखता। देश की बीमा कंपनियों वाले दौर से आगे कितनी प्रगति हुई है, सौ फीसदी मिल्कियत सौंपने से पहले इस पर विचार हुआ हो, ऐसा नहीं लगता।

लेकिन जिस चीज की असली चर्चा होनी चाहिए वह इन कंपनियों से मिलने वाले बीमा के दायरे का है। वह विदेशी नाम या बड़े ब्रांड का बीमा तो करेंगे लेकिन देसी और छोटे उद्यमियों के उत्पाद बीमा के दायरे से बाहर हो जाते हैं, इसे अभी सबसे अच्छी तरह बीमारी के इलाज के सिलसिले से समझा जा सकता है। नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों और बीमा कंपनियों का गठजोड़ हम सबके अनुभव के दायरे की चीज है। कल को मकान, दुकान, फर्नीचर, बरतन-बासन और हर चीज के बीमा में यह भेद दिखेगा और लगेगा कि विदेशी बीमा कंपनियां कुछ खास संगी साथियों की मदद करने आई है- आम लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। पर इससे भी ज्यादा घातक बात निवेश वाली कंपनियों का चुनाव है जो बहुत स्पष्ट ढंग से पक्षपात बढ़ाती हैं। पैसा हमारा आपका और निवेश का फ़ैसला इन कंपनियों के हाथ में जाने से कुछ कंपनियों की आश्चर्यजनक तेज वृद्धि का रहस्य समझा जा सकता है। सो वे तो शत-प्रतिशत विदेशी मिल्कियत के लिए बेचैन रही होंगी ही, हमारी सरकारें क्यों निरंतर उनका मिशन आगे बढ़ाने में लगी रही हैं, यह समझना खास मुश्किल नहीं होना चाहिए।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

एक से 15 जून के बीच होंगे तबादले

● पति-पत्नी की पोस्टिंग एक जगह रखने पर विचार होगा; गंभीर बीमार कर्मचारियों को भी रियायत

प्रदेश के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए 30,055 करोड़ रूपये की कैबिनेट स्वीकृति

भोपाल (नप्र)। डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति-2026 को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा था। सीएम और मंत्रियों की सहमति के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया।

कैबिनेट ने तय किया है कि पति-पत्नी की पदस्थापना एक स्थान पर रखने के मामलों में कार्यवाही की जाएगी। गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी स्थानांतरण में रियायत दी जाएगी। नोटशीट में ए प्लस कैटेगरी वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऐसे मामले तबादला नीति से बाहर रखे गए- मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि सीएम की ए प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक करने हैं। लंबित आवेदन निपटाए जाएंगे। इसे तबादला नीति में शामिल नहीं किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग रहेगी

नई नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग-अलग तय करने का प्रस्ताव है। अब तक दोनों को एक ही कोटे में शामिल किया जाता था, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तबादलों में बाधा आती थी। अब तक कुल कर्मचारियों के 10 से 15 प्रतिशत तक तबादलों की अनुमति दी जाती थी। इसमें स्वैच्छिक और आपसी तबादले भी शामिल होते थे, जिससे जरूरी प्रशासनिक फेरबदल प्रभावित होता था। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर वर्ष की तरह अलग रहेगी। जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग नीति जारी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से अलग व्यवस्था नहीं कर सकेंगे।

भोपाल में सीएम का ऐलान

रोजगार सहायकों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के जंबूरी मैदान पर ग्राम रोजगार सहायकों का सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कई घोषणाएं कीं। सीएम ने कहा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। बिना मांगे आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको जब काम का टारगेट देते हैं तो काम आप करो आपकी चिंता सरकार करेगी। ये आवश्वासन आपको दे रहा हूं। आप सबने पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की थी। तो 9 हजार से बढ़ाकर दोगुना 18 हजार किया था। अब पंचायत सचिव के रिक्त पदों के मामले में, आयु सीमा के मामले में, अनुकंपा के मामले में आपके जनप्रतिनिधियों की बैठक कराकर ठोस निर्णय लेने वाले हैं।

रोजगार सहायकों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल होगी- सीएम ने कहा- आपसे गांव के विकास की अपेक्षा करते

हैं। हमने रोजगार सहायकों की आयु सीमा 62 साल की है। जो बहनें रोजगार सहायक हैं उन्हें प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। ऐसे विषयों पर हम काम कर रहे हैं।

आपराधिक मामलों से बरी होने पर फिर मिलेगी नौकरी- सीएम ने कहा- किसी कारण से किसी रोजगार सहायक पर आपराधिक प्रकरण बन जाए और बाद में वो निर्दोष सिद्ध हो जाए तो उसे पुनः सर्विस में लेने की गारंटी हम सरकार के माध्यम से घोषणा करते हैं। जब कोई अपराध नहीं किया तो फिर क्यों बाहर करना? सबसे पहले आपके हितों के साथ सुरक्षा और सम्मान से गांव के विकास को जोड़कर देखने की दृष्टि हमने शुरु की है।

कार ने 3 महिला धर्मगुरुओं को कुचला, एक की मौत

दो गंभीर घायल

रीवा (नप्र)। रीवा में बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहीं तीन जैन महिला धर्मगुरुओं को कुचल दिया। हादसा में एक महिला धर्मगुरु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, मृत महिला धर्मगुरु की पहचान श्रुति मति माता के रूप में हुई है। वे सागर जिले की रहने वाली थीं। सतना से रीवा प्रवास पर आई थीं। हादसे में घायल हुई उपसमिति माता तमिलनाडु की निवासी हैं, जबकि आरिका माता जबलपुर की रहने वाली बताई गई हैं।

सड़क किनारे पैदल जा रही थीं धर्मगुरु- प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीनों महिला धर्मगुरु सड़क किनारे पैदल जा रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर उनकी तरफ आ गई और तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। कमिश्नर बीएस जामोद, डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र सूर्यवंशी और एसपी गुरुकरण सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने और स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। हादसे के बाद पूरे जैन समाज में शोक और आक्रोश का माहौल है।

शरद की सुबह

चौका और पूजा घर है
एकदम साफ-सुथरा
शेष घर कुछ उजड़ा-सा
बहुत से घरेलू उपकरणों पर
धूल जमी हुई
जिन्हें जुटाने के लिए जीवन में
किया अथक परिश्रम।
जोड़ना नहीं है कुछ
जो है वही पर्याप्त
बल्कि कुछ ज़्यादा ही।
ताप नहीं है
आग सारी बुझ चुकी
शीतल जल ने जगह ले ली उसकी
जिसमें निर्मल हँसी
तैरती है श्वेत कमलों की तरह।
शांति है यहाँ
सुदूर वीराने में स्थित
किसी प्राचीन मंदिर की शांति
चंदन और अगरबत्ती की सुगंध
सर्वत्र व्याप्त।
लगभग मौन
धीमी ज़िंदगी
मंथर गति से होते हैं सब काम
वृद्ध दंपती के घर में।
आँगन के पेड़ से पत्ते
एक-एक कर झरते हैं
नि:शब्द।

- **चंद्रशेखर साकल्ले**

नितिन नवीन की नई टीम में अन्नामलाई की एंट्री!

● बीजेपी की संभावित लिस्ट में कई चौंकाने वाले युवा नाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अगले हफ्ते अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। उनकी टीम के जो संभावित नाम हाथ लगे हैं, उनमें ज्यादातर युवा चेहरे हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और

पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई का है। नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी को पश्चिम बंगाल और असम में अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है। पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। चुनाव से पहले पांच राज्यों में से सिर्फ दो में ही एनडीए की सरकारें थीं, अब तीन राज्यों में गठबंधन ने भगवा लहरा दिया है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष पर गोवा और मणिपुर में चुनाव की जिम्मेदारी है।

आर्थिक तूफान सिर पर, प्रधानमंत्री मोदी इटली में टॉफी बांट रहे

● मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देने पर राहुल गांधी का तंज

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की। इसका वीडियो बनाकर इटली की पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर तंज कसा। आर्थिक तूफान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं! बता दें कि पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर भारत से रवाना हुए थे। जिसमें वह सबसे पहले यूएई गए थे। यहां कुछ घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री यूएई से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए थे। नीदरलैंड की यात्रा पूरी होने के बाद पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे और इसके बाद वह नॉर्वे रवाना हो गए थे। नॉर्वे की यात्रा पूरी होने के बाद अब प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हैं। यहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ही उन्होंने मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की है।

भारत इटली

मजबूत करेंगे रणनीतिक रिश्ते

● रोम से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, मेलोनी ने आईएमईसी पर दिया जोर

रोम (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली को भारत का अहम साझेदार बताया और कहा कि हमारी बातचीत तय एजेंडे से कहीं आगे की है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को देशों की पार्टनरशिप की इंजन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। इस दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को तेजी से विकसित करने पर जोर दिया।

आतंकवाद के खिलाफ भारत-इटली एक

पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और इटली एकमत हैं कि यह मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहले ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। पीएम मोदी बोले-भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जिम्मेदार लोकतंत्र आतंकी नेटवर्क तोड़ने में साथ रहेंगे।

● **इटली के साथ स्पेशल रणनीतिक साझेदारी का ऐलान-** उन्होंने कहा, पिछले लगभग साढ़े तीन साल में मुझे कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दिखाता है।

मेलोनी ने कहा ऐतिहासिक दिन

संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी को मित्र कहकर संबोधित किया और इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। मेलोनी ने

कहा, आज का दिन हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्र नरेंद्र मोदी 2014 से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज इटली की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले किसी भारतीय पीएम की इटली यात्रा 26 साल पहले हुई थी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 21 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

पीक पर गर्मी, झुलसा रहे 'लू' के थपेड़े

● अगले 7 दिन 10 राज्यों में चलेंगी गर्म हवाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में गर्मी अपने पीक पर है। इस बीच मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अरब सागर के ऊपर नया सिस्टम बनने की जानकारी दी है, जो मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है। इससे केरल समेत दक्षिण भारत में बारिश कम होने की आशंका है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी-गर्म हवाएं चलेंगी। एजेंसी के मुताबिक इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा रहेगा। वेस्टर्न

डिस्टर्बेंस कमजोर होने और कोई ऐक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है।

शहरों में फील टेंपरेचर 4 सेंटीग्रेट तक अधिक

वास्तविक तापमान और फील टेंपरेचर में हर शहर में औसत 2 से 4 डिग्री तक का अंतर है। क्लाइमेट एक्सपर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग जो तापमान बताता है, लोगों को उससे कहीं ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण तेजी से होता शहरीकरण है। इससे तापमान में उछाल आ रहा है। फील फैक्टर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत को भिगोने वाले दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ने मंगलवार को कोमरिन सागर, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी भाग के कुछ और हिस्सों को कवर कर लिया।

यूपी में अगले 5 दिनों तक चलेगी हीटवेव

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक पूरे प्रदेश में गर्मी रहेगी। आज हीटवेव का 11 जिलों में रेड, 14 जिलों में ऑरेंज और 28 जिलों में यलो अलर्ट है। ज्यादातर जिले लू की चपेट में रहेंगे। 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। दिन का तापमान 44 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं राजस्थान में गर्मी और हीटवेव का असर तेज हो गया है। सिरोही को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच रहा। जयपुर में रात की गर्म बनी हुई हैं। मंगलवार को यहां मिनिमम तापमान 31.3 रहा। बिहार में आज 33 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज और 18 में यलो अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश होती है तो अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास

● ट्रम्प के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की, राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50-47 से

● **ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नया कंट्रोल सिस्टम बनाया-** ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (जीएसए) बनाकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी। ईरान ने कहा कि बिना परमिशन गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरान ने साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और वह किसी दबाव में नहीं आएगा। राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने भी कहा कि बातचीत होगी, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं।

पास हुआ, हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो नहीं है।

ऑनलाइन बिक्री का विरोध सड़क पर दवा व्यापारी

● देशभर में 15 लाख मेडिकल स्टोर बंद कर जताया विरोध

नई दिल्ली (एजेंसी)। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कॉम्पटीशन के विरोध में बुधवार को देशभर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया

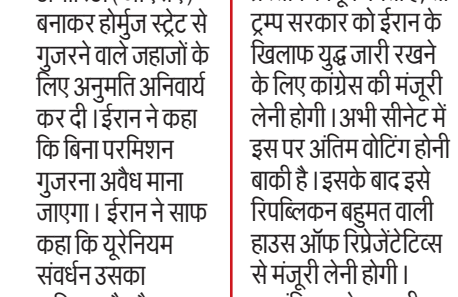

● **दवा दुकानदारों की 4 मांगें-** बिना नियमों के चल रही ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से मोहल्ले की छोटी दुकानों को नुकसान हो रहा है और लोगों की सेहत के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसे रोका जाए। इस पूरे विवाद से जुड़े सरकार के दो नियम हैं। संगठन के मुताबिक इन नियमों की कमियों का फायदा उठाकर ही ऑनलाइन दवा कंपनियां ऐसा कर रही हैं। इसे वापस लिया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत या नकली पर्चियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ई-फार्मेसी के लिए नए सख्त नियम बनाए जाएं। लोकल दुकानदार ऑनलाइन के विरोध में हैं।

ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। बंद का मामूली असर दिखा। पटना के एम्स के बाहर मरीज और उनके परिवार वाले दवाओं के लिए परेशान दिखे। वहीं, चंडीगढ़ के पीएनजी में इलाज कराने आए कश्मीर के एक परिवार को भी दवाई नहीं मिल सकी। उसने कहा, दवाएं नहीं मिल रही हैं। हालांकि, एजेंसी ने कहा था कि बंद के दौरान भी अस्पतालों से जुड़े स्टोर खुले रहेंगे।

उज्जैन के कालभैरव मंदिर में अब वीआईपी दर्शन व्यवस्था

500 रुपए देकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु; मंदिर के बाहर मिलेगा टिकट

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाद अब श्री काल भैरव मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। बुधवार से लागू हुई इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालु 500 रुपए का टिकट लेकर सीधे गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। टिकट मंदिर परिसर के बाहर बने काउंटर से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री कालभैरव मंदिर, जहां भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है, वहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बढ़ती श्रद्धालु संख्या और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को देखते हुए मंदिर में 125.17 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर

और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, फिलहाल यह व्यवस्था ऑफलाइन शुरू की गई है, जिसे जल्द ही ऑनलाइन भी किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को विशेष मार्ग से सीधे गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन की सुविधा मिलेगी।

ऐसे मिलेंगे शीघ्र दर्शन- काल भैरव मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल की सशुल्क दर्शन व्यवस्था के साथ सामान्य श्रद्धालु अगर शीघ्र दर्शन करना चाहता हैं तो उन्हें मंदिर के बाहर लगे टिकट काउंटर से 500 रुपए का टिकट लेना होगा।

इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर के निर्गम द्वार से लगे हुए मार्ग से प्रवेश मिलेगा, यहां से श्रद्धालु सीधे मंदिर के गर्भगृह द्वार के गेट से एंट्री लेकर सीधे गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे।

सिर्फ ऑफलाइन व्यवस्था अभी- काल भैरव मंदिर में प्रशासक एलएन गर्ग ने बताया कि अभी शुरुआत में ऑफलाइन टिकट वयवस्था की है। इसे जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यहां आने वाले श्रद्धालु शीघ्र दर्शन के नाम पर कई बार ठगी का शिकार होते थे।

युवती ने भागकर रिश्ते के चाचा से रचाई शादी

एसपी ऑफिस पहुंचकर मांगी सुरक्षा, कहा- हमारी जान को है खतरा

छतरपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती छतरपुर एसपी में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंची थी। युवती ने घर से भागकर रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक से शादी रचा ली है। इसके बाद युवती के परिवार वाले एसपी ऑफिस पहुंच गए।

दो अप्रैल को हुई थी लापता- दरअसल, युवती लवकुशनगर थाना क्षेत्र के गिलौहां गांव की रहने वाली है। दो अप्रैल को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गिलौहां निवासी मोहन सिंह यादव ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी प्रतिमा यादव 2 अप्रैल की रात अचानक घर से लापता हो गई थी। परिवार ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि युवती रिश्ते के चाचा धर्मेन्द्र यादव निवासी हंसपुरा के साथ चली गई है।

पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई- परिजनों का आरोप है कि मामले की शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई। परिवार का कहना है कि अक्टोंहा चौकी में पदस्थ एक पुलिसकर्मी ने उन पर 181 शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, कार्रवाई के नाम पर पैसों की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

देख ले दुनिया! चांद पर पहुंच गया 'सपेरों का देश'

अपनी कुंठा में मगन यूरोप, अभी और जलाएगी भारत की तरक्की

नई दिल्ली (एजेंसी)। हां, हम सपेरे हैं! और हमारी इस स्वीकारोक्ति में कोई शर्म नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए वैश्विक यथार्थ का सबसे बड़ा व्यंग्य छिपा है। हम वाकई सपेरे हैं, क्योंकि आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, युद्ध की विभीषिका और कूटनीतिक अस्थिरता के जहरीले फन के आगे खौफजदा है, तब नया भारत अपनी नीतियों की 'बीन' से इन सभी वैश्विक संकटों को काबू कर रहा है। हाल ही में नॉर्वे के एक अखबार ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक सपेरे के रूप में दर्शाते हुए जो कार्टून छापा है, वह कोई रचनात्मक व्यंग्य नहीं है। यह दरअसल उस यूरोपीय और पश्चिमी मीडिया की हताशा का प्रकटीकरण है, जो 19वीं सदी के 'कोलोनियल हैंगओवर' से आज तक बाहर नहीं आ सका है।

● **अंतरिक्ष से लेकर सिलिकॉन वैली तक- 'बीन' की नई धुन-** आज का भारत उस औपनिवेशिक ढांचे को तोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। नॉर्वे के अखबार या अन्य पश्चिमी मीडिया घरानों की यह कुंठा दरअसल भारत की वर्तमान सफलताओं को पचा न पाने का सीधा परिणाम है। जिस देश को वे दशकों तक दान और दया का पात्र मानते थे, आज वह उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग ने पश्चिमी देशों के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। जिस एलीट स्पेस क्लब पर पश्चिमी देशों का एकाधिकार था, भारत ने अपने स्वदेशी ज्ञान और बेहद कम बजट में उसके दरवाजे तोड़ दिए। अपना देश मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहली ही कोशिश में पहुंच गया है।

'सपेरों का देश' एक गढ़ी हुई छवि

भारत को सपेरों, हाथियों और जादूगरों का देश कहना कोई स्वाभाविक बात नहीं थी; यह 18वीं और 19वीं सदी के ब्रिटिश और यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा बेहद चालाकी से गढ़ा गया एक नैरेटिव था। इस एजेंडे का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध बौद्धिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विरासत को दुनिया की नजरों से छिपाना था। पश्चिमी देशों को यह साबित करना था कि पूर्व के देश 'असभ्य' हैं, ताकि वे दुनिया पर अपने शासन और लूट को 'वाइट मेन्स बर्डन' कहकर सही ठहरा सकें। प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने आंकड़े पेश किए हैं।

इतिहास का आईना और पश्चिमी कुंठा

पश्चिमी देशों ने सदियों तक 'वाइट मैन्स बर्डन' के नाम पर दुनिया को लूटा और अपने साम्राज्यवाद को सही ठहराने के लिए भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं की एक स्टीरियोटाइप छवि गढ़ी। सपेरों का देश, हाथियों का देश, जादू-टोने का देश- ये वे नैरेटिव थे जो उनके अखबारों और साहित्य ने बेचे। लेकिन वे यह भूल गए कि जब यूरोप अंधकार युग में जी रहा था, तब भारत तक्षशिला और नालंदा से दुनिया को ज्ञान बांट रहा था। आज नॉर्वे के अखबार का यह कार्टून उसी कुंठा की राख में सुलगती हुई ईर्ष्या है। उन्हें दर्द इस बात का है कि भारत अब उनका सपेरा बन गया है।

ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा

● टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को बना सकेगी निशाना

डीआरडीओ ने स्वदेशी कंपनियों के साथ कर दिया कमाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा कर लिया है। इस मिसाइल का नाम यूएलपीजीएम-वी3 है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे हवाई टारगेट को मार गिरा सकती है।

वहीं जमीन पर टैंक, सैन्य वाहन और बंकर को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित टेस्ट रेंज में किया गया। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो लॉन्च और कमांड सिस्टम को कंट्रोल करता है।

● **चलते-फिरते टारगेट को भी लॉक कर सकती है-** यूएलपीजीएम-वी3 एक स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। इसमें सीकर तकनीक लगी है, जिससे यह टार्गेट को पहचानकर लॉक करती है और फिर सटीक हमला करती है। चलते हुए लक्ष्य को भी ट्रैक कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इसे एंटी-टैंक रोल के लिए भी तैयार किया गया है। साथ ही यह ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई लक्ष्यों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है।

बिजली बिल वसूली में नहीं करें कोताही : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

ऊर्जा मंत्री ने की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यों की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। कम्पनी की आय बढ़ाने के लिये आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। बिजली बिलों की वसूली में कोताही नहीं करें, लेकिन शुरूआत बड़े उपभोक्ताओं से करें। आवश्यकता अनुसार कॉलोनियों में वसूली शिविर भी लगायें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश मंत्रालय में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये।

अच्छा कार्य करने वालों को मिले बेहतर पोस्टिंग- ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि खराब स्थानों पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को बेहतर पोस्टिंग दें। इससे अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण के लिये कार्य-योजना बनायें। बैठक में बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल भुगतान में सुधार आया है। मध्य क्षेत्र में 10 लाख 60 हजार स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस बात की सतत समीक्षा करें कि जिस क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं, वहाँ बिजली बिलों के भुगतान की स्थिति में कितना सुधार हुआ है।

ट्रांसफार्मर फेल्योर की दर कम करें- ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफार्मर फेल्योर की संख्या कम से कम करें। ट्रांसफार्मर फेल्योर की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी करें।

फाल्टा में किरकिरी, अब 43 प्रॉपर्टी की लिस्ट जारी

मुश्किल में फंसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी

केएमसी का नोटिस, प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों का शिकंजा

कोलकाता (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के नंबर-2 और टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। फाल्टा उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फाल्टा विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। इससे पहले सोमवार

शाम को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन पर नोटिस चिपकाया है जिसमें 17 प्रॉपर्टी का जिक्र है।

● **अभिषेक बनर्जी को फाल्टा में मिली थी 1.68 लाख की लीड-** पहली बात फाल्टा उपचुनाव की। वोटिंग से पहले टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के पैर खींचने से टीएमसी की ज्यादा किरकिरी हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की धमकियों के कारण जहांगीर बैकफुट पर गए। फाल्टा विधानसभा सीट अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। 2024 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से सात लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। फाल्टा विधानसभा से उन्हें 1.68 लाख वोटों की लीड मिली थी।

मध्यप्रदेश में पहली बार लू का रेड अलर्ट

देश में बुंदेलखंड सबसे गर्म,नौगांव में 47 डिग्री पारा, 22 शहरों में 44 डिग्री पार, आज वॉर्म नाइट की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सहित देश में भीषण गर्मी बेहाल कर रही है। बीते 24 घंटे में महज 120 किलोमीटर की दूरी पर बसे यूपी के बांदा और मध्य प्रदेश के नौगांव में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। बांदा में जहां 48 डिग्री तापमान रहा तो एमपी के नौगांव में 47 डिग्री तापमान रहा। आईएमडी ने एमपी में अगले 4 दिन भीषण लू का रेड अलर्ट दिया है।

राजधानी भोपाल में रिकार्ड तोड़ गर्मी - देश के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी पड़ रही है। बुंदेलखंड का इलाका देश में सबसे गर्म इलाका दर्ज हुआ है। यूपी के बांदा में बीते 24 घंटों में जहां 48.2 डिग्री तो एमपी के नौगांव में 47 डिग्री तापमान रहा। यह देश में सबसे अधिक है। आईएमडी ने सीजन में पहली दफा एमपी के बुंदेलखंड के छह जिलों सहित भिंड में भीषण लू का रेड अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा लगभग पूरे प्रदेश में तीव्र लू का प्रभाव का ऑरेंज अलर्ट है।

मध्यप्रदेश इस समय भीषण गर्मी और प्री-मानसूनी बदलाव के दोहरे दौर से गुजर रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। नौगांव 47 डिग्री के साथ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश

के सबसे गर्म स्थानों में शामिल रहा, जबकि खजुराहो 46.4 डिग्री, दतिया 45.8 डिग्री, राजगढ़ 45.6 डिग्री और सागर 45.2 डिग्री तक पहुंच गए।

भोपाल में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री- राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने से रातों में भी गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में 'वर्म नाइट कंडीशंस' विकसित हो रही हैं, जिससे दिन और रात दोनों समय गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।

मध्य प्रदेश में सूरज जैसे आग उगल रहा है। दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है तो लू के थपेड़ों का सितम भी है। मंगलवार को छतरपुर के 2 शहर- खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे। नौगांव में तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री रहा। सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 47 डिग्री पर पहुंचा। मौसम केंद्र ने अगले 4 दिन हीटवेव यानी, लू की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर में सीजन में पहली बार तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 44.2 डिग्री, इंदौर में 43.7 डिग्री, उज्जैन में 43.8 डिग्री और जबलपुर में 44.6 डिग्री रहा। भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा।

अगले 3-5 दिन कैसे रहेंगे?

उत्तर और पश्चिम मध्यप्रदेश में लू और तीखी गर्मी जारी रहेगी। पूर्वी एवं दक्षिणी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट संभव है, विशेषकर बारिश वाले क्षेत्रों में।

प्री-मानसूनी गतिविधियां होंगी तेज- मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी उत्तरप्रदेश से लक्षद्वीप तक बनी द्रोणिका (ट्रफ लाइन) मध्य भारत से होकर गुजर रही है। इसके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हो रही है। यही वजह है कि दक्षिण एवं पूर्वी मध्यप्रदेश में प्री-मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया और नर्मदापुरम संभाग के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान शाम या रात में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है।

ई-रिक्शा से कैबिनेट बैठक के लिए मंत्रालय पहुंचे मंत्री द्वय टेटवाल और पंवार

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से किए गए ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को आत्मसात करते हुए, बुधवार को कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचे।

सुरक्षित पर्यावरण का यही आधार-ईंधन बचत हर बार का संदेश देते राज्यमंत्री श्री टेटवाल कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसाधनों के संयमित उपयोग का जो आह्वान किया है, उसे आत्मसात कर हम सभी को अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए।

ऊर्जा बचत को जन आंदोलन बनाने की अपील- मंत्री श्री टेटवाल और श्री मंत्री पंवार ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और ऊर्जा बचत को एक जनआंदोलन बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे-छोटे प्रयास ही भविष्य में एक आत्मनिर्भर, स्वच्छ एवं सशक्त भारत के निर्माण की मजबूत नींव तैयार करेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्व. मल्हारराव होल्कर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होल्कर राजवंश के संस्थापक स्व. मल्हारराव होल्कर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे संपूर्ण राष्ट्र के गौरव हैं। उन्होंने मालवा की माटी को अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम से सींचा। होल्कर राजवंश लोक-कल्याण और जनसेवा के लिए जाना जाता है। हम सभी उनसे प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

महिला गांजा तस्कर सहित सात गिरफ्तार

ट्रेन से लाती थी गांजा, 36 किलो माल जब्त

भोपाल (नप्र)। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने ट्रेन से गांजा लेकर आ रहीं पांच महिला समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 36 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंजाब मेल ट्रेन से गांजे की बड़ी खेप आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रेन से उतरते ही दो महिला समेत सात लोगों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास से करीब 36 किलो गांजा मिला। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घरेलू सामान भी रखा हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम राहुल, रवि, रचना, सीमा, निधि, काजल और आरती बताया। ये सभी आरोपी छोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और पुराने गांजा तस्कर हैं। इसके अलावा पुलिस ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास इतनी भारी मात्रा में गांजा कहां से आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

प्रदेश के 41 हजार मेडिकल स्टोर्स बंद

बुजुर्ग भटकते रहे...दवा नहीं मिली, भोपाल में जलाया पुतला, दवा की ऑनलाइन बिक्री का विरोध

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बुधवार को करीब 41 हजार दवा दुकानें बंद हैं। अकेले भोपाल में 3 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स इस बंद में शामिल हैं। सिर्फ अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स को ही खुला रखा गया है। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स की ओर से ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुलाया गया है।

आईओसीएडी को जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंघल ने बताया कि प्रदेश के सभी रिटेल और थोक दवा व्यवसायियों ने इस बंद का

समर्थन किया है। यह मुद्दा सीधे आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। घर-घर पहुंच रही ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी स्पष्ट सिस्टम नहीं है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इधर, भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ का कहना है, आज भोपाल के सभी मेडिकल स्टोर्स बंद है। थोक दवा बाजार भी बंद रखा गया है। बाजार में ऑनलाइन सिस्टम का पुतला भी दहन किया है।

हड़ताल से मरीज होते रहे परेशान -ग्वालियर के दवा बाजार में दवा लेने पहुंचे बुजुर्ग हरिओम कश्यप ने बताया कि वह अपनी 75 साल की पत्नी के लिए दवा लेने आए थे, लेकिन बाजार बंद होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर भटकने पर भी उन्हें दवा नहीं मिलीं। उन्होंने कहा कि जिस दवा के लिए वह आए हैं, वह उनकी पत्नी के लिए बेहद जरूरी है। समय पर दवा नहीं मिलने से उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है।

अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स बंद से मुक्त - अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स को बंद से मुक्त रखा गया है, ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। इमरजेंसी मरीजों के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है। संपर्क के लिए नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल कर मरीज दवा की मांग कर सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल महंगे प्रदेश में 10 प्रतिशत बढ़ेगा माल भाड़ा

2 महीने में दूध, खाना-एलपीजी के रेट भी बढ़े, एक्सपर्ट बोले-भाड़े से महंगाई और बढ़ेगी

भोपाल (नप्र)। पांच दिन के अंदर पेट्रोल-डीजल की कीमतें 4 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गईं। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने मध्य प्रदेश में माल भाड़ा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में माल भाड़ा 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते पहले ही दूध, खाना और एलपीजी महंगे हो चुके हैं। अब भाड़े में बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट गड़बड़ाना तय है।

भोपाल के बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी कमल पंजवानी ने मीडिया को बताया कि सरकार की नीतियों के चलते ट्रांसपोर्ट सेक्टर पहले ही ऑक्सीजन पर है। अब डीजल के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे कारोबार प्रभावित हो सकता है।उदाहरण के तौर पर यदि भोपाल से इंदौर के बीच का भाड़ा 10 हजार रुपए है तो यह बढ़कर 11 हजार रुपए हो सकता है। एमपी में 8 से 10 लाख ट्रक चलते हैं, जो ऑल इंडिया परमिट वाले होते हैं, यानी ये पूरे देश में कहीं भी माल लाने-ले जाने का काम करते हैं।

माल भाड़ा बढ़ा तो महंगा होगा सामान- ट्रक व लोडिंग वाहनों से पूरे प्रदेश में किराना, सोयाबीन, कपास, गेहूं, सीमेंट, चूना पत्थर, दवाएं, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर पैनल, खाद आदि की सप्लाई की जाती है। माल भाड़ा बढ़ने से इन सामानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कारोबारी कमल पंजवानी ने बताया कि भाड़ा बढ़ने का असर आखिरकार जनता पर ही होगा।

किचन से जुड़ा सामान महंगा हो चुका- किराना कारोबारी विवेक साहू कहते हैं कि ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद बाजार में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें बढ़ी हैं। इससे जनता के बजट पर असर पड़ा है। माल भाड़ा बढ़ता है तो तय है कि कीमतें और भी बढ़ जाएंगी।

टैक्सी संगठन की बैठक अगले सप्ताह- ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय सचिव नफीस उद्दीन ने बताया कि संगठन और टैक्सी चालकों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। अगले एक सप्ताह में बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें 10 से 20 प्रतिशत तक किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक के बाद ही तय होगा कि किराया कितना बढ़ाया जाए।

खाना महंगा, होटल और रेस्टॉरेंट में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी

भोपाल होटल एवं रेस्टॉरेंट संघ के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली बताते हैं कि होटल इंडस्ट्री पहले ही एलपीजी संकट से जूझ रही है। 2 महीने के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ गए। अब यह करीब 3 हजार रुपए में मिल रहा है। एलपीजी संकट के बाद भोपाल में भोजन 10 से 15 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। दूध के रेट 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। इस वजह से पनीर और दही भी महंगे हो गए, जिसका असर सीधे खाने के मेन्यू पर पड़ा है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक होगी उज्जैन में : मुख्यमंत्री यादव

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह बैठक के बाद सिंहस्थ की तैयारियों का करेंगे मुआयना

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली (27वीं) बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद् की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक लेने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक बस्तर में करके देश में नक्सलवाद की समाप्ति का जन संदेश दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण से बीते सप्ताह राज्य में हुई विशेष गतिविधियों और सरकार को मिली उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की।

मध्यप्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधिकारी सम्मानित, मुख्यमंत्री ने दी बधाई- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को नक्सल मुक्त करने में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह द्वारा पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव सहित 'नक्सल उन्मूलन अभियान' में सक्रिय योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है।

भोजशाला पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत, मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा लाने का प्रयास करेगी सरकार- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले की भोजशाला परिसर को लेकर

मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने करीब 750 साल पुराने और धार्मिक/ईश वंदना से जुड़े इस मसले का सकारात्मक एवं शांतिपूर्ण समाधान किया है। सरकार इस विषय से जुड़े सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करायेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार मां वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा विदेश से स्वदेश लाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ हर जरूरी प्रयास एवं समन्वय करेगी।

ब्रिक्स राष्ट्र नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक सहयोग के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं : मंत्री सारंग

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स यूथ इन्ट्रेप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग-2026 को संबोधित करते हुए कहा कि आज ब्रिक्स राष्ट्र विकासशील देशों की आकांक्षाओं, ऊर्जा, नवाचार क्षमता एवं आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, अतिरिक्त सचिव श्री नितेश कुमार मिश्रा, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप लीडर्स, नीति निर्माता, शिक्षाविद् एवं युवा उद्यमी उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्री सारंग ने कहा कि भारत सदैव शांति, साझेदारी, मानवीय मूल्यों एवं वैश्विक सहयोग में विश्वास रखने वाला देश रहा है। उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम् - विश्व एक परिवार है की भारतीय अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत विरासत विश्व को सद्भाव, समावेशी विकास एवं सामूहिक कल्याण की दिशा प्रदान करती रही है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत नवाचार, उद्यमिता, युवा सशक्तिकरण, जलवायु उत्तरदायित्व एवं ग्लोबल साऊथ के विकास के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में तेजी से उभर रहा है।

देर रात तक जारी धरना, कोर्ट से जीत के बाद भी जॉइनिंग नहीं मिलने पर आक्रोश

जेपी हॉस्पिटल परिसर में रातभर धरने पर डटीं एएनएम अभ्यर्थी

भोपाल (नप्र)। राजधानी के जयप्रकाश हॉस्पिटल, तुलसी नगर स्थित संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय परिसर में एएनएम अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। मंगलवार को दिनभर धरना देने के बाद भी 20-25 महिलाएं रात में भी वहीं डटी रहीं। भीषण गर्मी के बावजूद उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

धरने में शामिल महिलाएं खुले आसमान के नीचे देर रात तक बैठी रहीं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करती रहीं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें नियमित नियुक्ति (जॉइनिंग) नहीं दी जाती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगी।

अभ्यर्थियों के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2023 में एएनएम के नियमित पदों के लिए आवेदन किया था और भर्ती प्रक्रिया में हुई विसंगतियों के खिलाफ कोर्ट

का रुख किया था। कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है।

प्रदर्शनकारी ममता हिरवे ने बताया कि वे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुकी हैं, यहां तक कि 9 दिन का आमरण अनशन भी किया गया था। उस दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द जॉइनिंग दी जाएगी, लेकिन 9 माह बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा जारी सूचियां सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई हैं और उनमें बार-बार उन्हीं नामों को दोहराया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। वहीं, वर्षों से संविदा में सेवाएं दे रहीं और कोविड काल में काम कर चुकी अभ्यर्थियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

महिलाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जा रहा है और न्यायपालिका के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में वे अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। रात में भी जारी इस धरने ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि, अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है।

संपादकीय

अडाणी को क्लीनचिट के मायने!

भारतीय उद्योगपति गौतम अडाणी को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा उन पर लगे आर्थिक घोटालों के आरोपों के बाद हुई 'वित्तीय डील' के पश्चात मिली क्लीन चिट को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बताया जाता है कि गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणी ने अमेरिका में चल रहे मुकदमे को निपटाने के लिए संयुक्त रूप से 1.80 करोड़ डॉलर का जुर्माना देने पर सहमति दी थी। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने सारे अडाणियों पर लगे सारे आपराधिक आरोप वापस ले लिए हैं। साथ ही न्यूयॉर्क में चल रहा हाई-प्रोफ़ाइल सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड मामला पूरी तरह बंद हो गया है। गौरतलब है कि अमेरिका के सिक्योरिटीज रेगुलेटर (नियामक) ने 2024 को दायर मुकदमे में अडाणी परिवार पर निवेशकों को कथित तौर पर गुमराह करने का आरोप लगाया था। इसके मुताबिक अडाणी परिवार ने इस तरीके से अमेरिकी निवेशकों से लगभग 17.5 करोड़ डॉलर समेत 75 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई थी। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को 'बेबुनियाद' करार दिया। उधर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक बयान में पुष्टि की कि ऑफ़िस ऑफ़ फ़ॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफ़एसी) ने अडाणी एंटरप्राइज़ेज़ लि. (एईएल) के साथ 27 करोड़ 50 लाख डॉलर के समझौते की घोषणा की है। इस समझौते पर 14 मई 2026 को हस्ताक्षर हुए थे। एईएल ने, ओएफ़एसी के ईरान प्रतिबंधों के 32 संभावित सिविल उल्लंघनों को लेकर अपनी ज़िम्मेदारी के निपटारे पर सहमति जताई। अदालत में दायर दस्तावेज में अमेरिकी न्याय विभाग ने अदानी परिवार पर आरोपपत्र को स्थायी रूप से ख़ारिज़ करने की मांग की है। यह मामला दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। यह फैसला उस मामले में बड़ा मोड़ माना जा रहा है, जिसने अदानी समूह की वैश्विक विस्तार योजनाओं पर असर डालने की आशंका पैदा कर दी थी। इस फैसले के बाद अडाणी समूह का मार्केट कैप एकदम 7 लाख करोड़ रू.बढ़ गया। जहां तक भारत की बात है तो अडाणी को गुजराती होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। यही कारण है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडाणी पर लगातार हमले करते रहे हैं। लेकिन अब अडाणी को क्लीनचिट मिलने के बाद उनका यह अस्त्र भी बेकार हो गया लगता है, जैसे कि राफेल डील मामले में लगाए आरोपों के कारण हुआ था। आश्चर्य नहीं कि इस फैसले के बाद अडाणी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दें। हालांकि जो डील हुई है, उसमें खुद अडाणी ने उन पर लगे आरोपों को खारिज नहीं किया है। वैसे इस डील के बाद राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम मोदी को लपेटा है कि उन्हीं के चलते अडाणी की यह डील संभव हुई है। इसका अर्थ यही है कि राहुल को अमेरिकी न्याय व्यवस्था का पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि सिर्फ मोदी के कहने अथवा दबाव डालने पर ऐसी कोई डील संभव होती तो भारत के बहुत से मसले ऐसे हैं, जिनमें अमेरिका को समझौता कर लेना चाहिए। अर्थात् अडाणी कोई दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी को ऐसे गंभीर आरोप लगाने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। वरना ज्यादातर मामलों में उन्हें कोर्ट में माफी ही मांगनी पड़ी है। इससे उनकी सुधरती राजनीतिक छवि को झटका लगता है। भले ही वो खुद इससे बेफिकर दिखने का संदेश देने की कोशिश करें। इसमें संदेह नहीं कि अडाणी को निशाना बनाने के पीछे राहुल के वामपंथी सलाहकार ज्यादा थे। जबकि राहुल यह काम किसी छोटे नेता से भी करा सकते थे। खुद उनकी पार्टी में अडाणी को टारगेट करने को लेकर एक राय नहीं थी। अलबत्ता अडाणी केस इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं।

नजरिया

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वेनेजुएला के बाद क्या क्यूबा की बारी है

"अमेरिका की आँखों में
मिर्ची सा लगता है
हवाना के सिगार का धुआँ"
(लंबी कविता 'बीसवीं सदी इक्कीसवीं सदी से')

यह आज की बात नहीं है, बल्कि बीती कई दहाइयों से अमेरिका के लिये बुकनी सा कष्टप्रद यह सिलसिला जारी है। दरअसल यह तकलीफदेह क्रम सन् 1959 में फिदेल कास्त्रो के कू-दे-ता के जरिये सत्ता में आने के ऐन दिन से शुरू हो गया था। फिदेल को अपदस्थ करने अथवा मारने की सीआईए की सारी कोशिशें विफल रहीं। अमेरिका उनकी मुश्कें नहीं कस सका। उलटे फिदेल वैश्विक नेता के तौर पर उभरते गये और उन्होंने दुनिया भर के मुक्तिकामी जनों को आकर्षित किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और क्यूबा के संबंधों को नयी ऊंचाई और सान्द्रता मिली। शीतयुद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा को मुसीबतों से दो-चार होना पड़ा। रही सही कसर अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों ने पूरी कर दी। जारी वर्ष के प्रारंभ में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के निर्लज्ज अपहरण से अनेक छोटे और निर्बल राष्ट्र सकते में आ गये। यूं तो 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के अभीष्ट की पूर्ति के लिये ही अमेरिका ने इस्रायल के सहयोग से 28 फरवरी को ईरान पर धावा बोला था और उसे अली खामेनेई समेत अनेक बड़े ईरानी नेताओं को मारने में कामयाबी भी मिली, अलबत्ता उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। अब यह सवाल सारी दुनिया में खतरे की घंटी की मानिंद घनघना रहा है कि क्या वेनेजुएला और ईरान के बाद अब बारी क्यूबा की है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशना कठिन इसलिये नहीं है क्योंकि जिद्दी और अड़ियल डोनाल्ड ट्रंप अपनी खब्त में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के 14 मई को हवाना की यात्रा और खुलेआम अंतिमेत्थम ने अमेरिका-क्यूबा के कसैले संबंधों मंह इजाफा कर एक करोड़ से कुछ अधिक क्यूबावासियों की रगों में सिहरन पैदा कर दी है।

आज नहीं, अर्से से क्यूबा के नसीब में चैन नहीं है और अमेरिकी धौंस, दबंगई और दादागिरी से उसकी मुसीबतों की गठरी भारी होती जा रही है। राजधानी हवाना समेत पूरा क्यूबा अंधेरे में डूबा हुआ है। क्यूबा अभूतपूर्व ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। डीजल और पेट्रोल का भंडार खत्म हो गया है। उसका अपना तेलशोधक संयंत्र फरवरी में आग की भेंट चढ़ गया। तेल की आपूर्ति के लिये उसका मुख्य आलंबन वेनेजुएला था, मगर अब वेनेजुएला अमेरिका का बंधक राष्ट्र है। ऊर्जा संकट का असर, शिक्षा, आहार, चिकित्सा आदि की प्रणालियों पर भी पड़ रहा है। हालत यह है कि राजधानी हवाना में नागरिकों को बाईस-बाईस घंटे ब्लैक आउट का सामना करना पड़ रहा है स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हैं और लोगों को खाना पकाने के लाले पड़ गये हैं। फलतः असंतोष गहरा रहा है और मुसीबतज़दा लोग सड़कों पर उतर रहे हैं।

क्यूबा के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो बीते करीब पांच शतियों में उसके संघर्ष की तस्वीर उभरती है। 20 अक्टूबर, सन् 1492 को कोलंबस की खोज के बाद यह कैरेबियन-द्वीप समूह स्पेन का उपनिवेश रहा। सन् 1868 में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की और सन् 1895 में आजादी की लड़ाई छेड़ी। सन् 1898 में उसे मान्यता तो मिली, लेकिन वह

अमेरिका के चंगुल में फँस गया। इसका अंत अंततः मई, 1902 में हुआ, जब वह गणतंत्र बना। लेकिन यह सौभाग्य भी अधिक दिन टिका नहीं। सन् 1933 में कूदेता से बातिस्ता सत्ता में आये और करीब पाव सदी क्यूबा ने उनकी तानाशाही झेली। इससे उसे आखिरकार सन् 1959 में फिदेल कास्त्रों ने मुक्ति दिलाई। फिदेल अपनी पॉलिसी से अमेरिका की आँखों की सबसे कर्री किरकिरी बनकर उभरे। अमेरिका ने उन्हें हटाने और निपटाने के लाख जतन किये, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। फिदेल दशक-दर-दशक उसकी छाती पर मूंग दलते रहे। उन्होंने महाबली अमेरिका की नाक तले कम्युनिस्ट रिजीम खड़ी कर दी। सन् 1962 का मिसाइल प्रसंग दुनिया भूली नहीं है। यह शीत युद्ध का चरम प्रसंग था। बहरहाल, कास्त्रों ने शिक्षा, चिकित्सा और आवास पर खूब ध्यान दिया। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सस्ते मकानों से उन्होंने क्यूबा का हुलिया बदल दिया। उन्होंने अफ्रीकी देशों व अन्यत्र डॉक्टरों की टोलियां भेजीं और दुनिया में अमेरिकी शिकंजे को तोड़ने का भरसक प्रयास किया। फलतः विश्व में मुक्ति कामी का जनता का यह लाड़ला नायक अमेरिका के लिये 'मोस्ट वांटेड' और खलनायक हो गया। उसके कृत्यों में सोवियत संघ उसका सरपरस्त और सहयोगी रहा। आज भी रूस और चीन उसके सहयोगी राष्ट्र हैं। रूस ने इसी साल 30 मार्च को एक लाख टन कच्चा तेल भेजा और चीन ने 80 मिलियन डॉलर की मदद और 60 हजार टन चावल देने का ऐलान किया। इसी क्रम में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आठ मिलियन और फिर साढ़े पांच मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की।

क्यूबा के खिलाफ वाशिंगटन के दबाव के चलते लातिनी अमेरिकी देशों में क्यूबा से कन्नी काटने का दायरा बढ़ता जा रहा है। मेक्सिको की क्लाडिया शीनबाम क्यूबा समर्थक हैं, लेकिन फरवरी में तेल से लदे दो पोत भेजन के पश्चात उन्होंने ट्रंप की नाराजगी के भय से क्यूबा को मदद से हाथ खींच लिये हैं। अर्जेंटिना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई अमेरिका के समर्थन में हैं, तो ब्राजील के लूला डिसिल्वा असमंजस में। चीले के गैब्रियल बोरिस ने क्यूबा पर पाबंदी को आपराधिक करार दिया था, लेकिन नये राष्ट्राध्यक्ष जोस अंतोनिया ने दो टूक कह दिया है कि क्यूबा को मदद से वहां तानाशाही के पाये मजबूत होंगे। अमेरिकी दबाव का असर अन्यत्र भी हो रहा है। निकारागुआ ने क्यूबनों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है, तो ग्वाटेमाला ने क्यूबा की मेडिकल ब्रिगेडों की चरणबद्ध वापसी का कदम उठाया है। इसी क्रम में इक्वेडोर ने क्यूबा के राजदूत वसीलो गुटीरेज को देश निकाला दे दिया है। ट्रिनिडाड-टोबैगो की कमला प्रसाद बिसेसर ने मानवीय सहायता की बात करते हुये पुछल्ला जोड़ दिया है कि वह तानाशाही का समर्थन नहीं कर सकतीं। योरोपीय राष्ट्र पुर्तगाल ने तो दो कदम आगे बढ़कर क्यूबा में टूरिस्ट-ऑपरेशंस बंद कर दिये हैं।

किस्सा कोताह यह है कि क्यूबा की मुसीबतों का अंत नहीं है। कास्त्रो-काल के वैश्विक समीकरण बदल चुके हैं। अमेरिका और क्यूबा के दरम्यां अतीत त्रिभंगी मुद्रा में खड़ा है। अमेरिका निकारागुआ और बोलीविया में विद्रोह को समर्थन और कांगो, इथियोपिया, अंगोला, मोजंबीक, गीनिया बिसाऊ, यमन, अल्जीरिया, इराक और सीरिया के मामलों में क्यूबा के दखल को भूला नहीं है। उसे सन् 1959 का पनामा-प्रसंग भी याद है, जब क्यूबा ने तख्ता पलट के प्रयासों में मुंह की खाई थी। दिलचस्प बात है कि क्यूबा ने तख्ता पलट में मुंह की खाने के बाद भी अमेरिका को मुंह बिराना नहीं छोड़ा।

ये ही वे प्रसंग हैं, जिन्होंने आज नव उपनिवेशवादी अमेरिका की भृकुटि में बल डाल रखे हैं। व्हाइट हाउस आज हवाना से पुराना हिसाब चुकता करने के मूड में है। वह गड़े मुर्दे उखाड़ते हुये सन् 1996 के चार विमानों के शूट आउट प्रसंग में तत्कालीन रक्षा मंत्री रऊल कास्त्रो पर अभियोजन के पक्ष में है। रऊल अब 94 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका उनके खिलाफ मुकदमे पर अड़ा हुआ है। क्यूबा भी अमेरिका की मंशा को भाँप रहा है, लिहाजा उसने अपना लहजा नरम कर दिया है। राष्ट्रपति मिगुएल डाएज कैनेल अमेरिकी कार्रवाई को समाज को व्यथित और बंधक बनाने तथा तख्तापलट की कोशिश मानते हुए 'जीनोसाइड' करार देते हैं, लेकिन अब वह निःशर्त बातचीत के लिए तत्पर दीखते हैं। इसी मार्च में उन्होंने 51 राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी की है। उधर रैटक्लिफ ने आर्थिक व सुरक्षा के मुद्दों पर ट्रंप की नीति से हवाना को अवगत कर दिया है। क्यूबन-अमेरिकी मूल के मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा ने 100 मिलियन डॉलर की अमेरिका की मानवीय सहायता ठुकरा दी है, तो क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगज परीला ने कहा कि अमेरिका ने ऐसी किसी मदद की पेशकश ही नहीं की।

क्यूबा में अमेरिका की नीयत का पता कतिपय सीनेटरों के बयानों से लगता है। सीनेटर रिक स्कॉट कहते हैं कि क्यूबा में लोकतंत्र की वेला आ गई है, तो लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि क्यूबा में वर्तमान सत्ता के दिन इनेगिने हैं। जॉन थूने आक्रमण की पैरवी तो नहीं करते, किंतु 'सरकार गिरी तो खुश होगी' कहकर मंशा दर्शा देते हैं। क्यूबन-अमेरिकी मूल के टेड क्रूज ने तो फरवरी में ही कह दिया था कि आगामी छमाही में वेनेजुएला, ईरान और क्यूबा में सत्ता परिवर्तन होगा। क्यूबा के अर्नेस्टो सोबेरान गजमान और लिआनिस टोरेस रिवेरा जैसे राजनयिक भले ही मुट्ठियां बांधकर संघर्ष का दम भरें, लेकिन सब जानते हैं कि अमेरिका से रण में मुकाबला कठिन होगा। यूएनओ के महासचिव गुटरेज नाकेबंदी की निंदा करते हुए भी स्वयं को असहाय पाते हैं। अमेरिका रऊल कास्त्रो के पौत्र रऊल गुलिर्मो रोड्रिग्रेज कास्त्रो पर दांव लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्यूबा के मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण की बात करते हैं तो साफ हो जाता है कि देगची में क्या पक रहा है? बेलोरूस, ईरान, वियेतनाम और अफ्रीक यूनियन भले ही क्यूबा के साथ हो, लेकिन ट्रप का विश्व-जनमत से प्रभावित होना मुमकिन नहीं दीखता। बहुत संभव है कि ईरान का मोर्चा ठंडा पड़ते ही वह वेनेजुएला की तर्ज पर क्यूबा का टेंटुआ दबोच लें।

क्या राष्ट्रहित से ऊपर है राजनीति?

ग्रेट निकोबार

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लेखक पत्रकार हैं।

आज जब भारत विश्व मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, तब देश को मजबूत सामरिक ढांचा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक व्यापारिक क्षमता की भी आवश्यकता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को अपने समुद्री हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना समय की मांग है। ऐसे समय में ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के सामरिक, आर्थिक और वैश्विक भविष्य की आधारशिला है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस परियोजना का लगातार विरोध कर रही है। वस्तुतः कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी आदिवासी हितों के नाम पर और अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रश्न उठाकर कांग्रेस एक ऐसे प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, जोकि भविष्य में भारत को समुद्री शक्ति, व्यापारिक आत्मनिर्भरता और सामरिक मजबूती प्रदान करने का कारण बनेगा। सवाल यह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस को पर्यावरण और जनजातीय समाज की इतनी चिंता है या फिर यह मोदी सरकार का विरोध करने की योजनाबद्ध मानसिकता है?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अब हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार परियोजना के मौजूदा स्वरूप पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका तर्क है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और टाउनशिप जैसी योजनाएं सैन्य क्षमता नहीं बढ़ातीं और पर्यावरण तथा आदिवासी समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसे में यहां स्वाभाविक प्रश्न उभरता है कि यदि कांग्रेस को विकास परियोजनाओं से इतना ही परहेज है, तब अपने दशकों लंबे शासनकाल में उसने देशभर में हजारों बड़े बांध, बंदरगाह, औद्योगिक कॉरिडोर, राजमार्ग और शहरी परियोजनाएं क्यों शुरू कीं? क्या तब पर्यावरण और जनजातीय हित याद नहीं आए? क्या उस समय पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा था? असल सच्चाई यह है कि कांग्रेस का यह विरोध सिद्धांत आधारित न होकर सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। यदि यही परियोजना कांग्रेस सरकार लेकर आती, तो वही नेता इसे 'भारत के भविष्य का द्वार' बताते।

वस्तुतः यह सभी समझें कि ग्रेट निकोबार द्वीप की स्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से मात्र लगभग 40 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक के इतना निकट होना भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अमूल्य अवसर है। आज भारत का बड़ा हिस्सा विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों, जैसे कोलंबो, सिंगापुर और क्लांग पर निर्भर है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत का व्यापारिक और सामरिक हित दूसरे देशों की बंदरगाह नीतियों पर निर्भर रहता है। ग्रेट निकोबार परियोजना इस निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम है। हमें समझना होगा कि 14.2 मिलियन टीईयू क्षमता वाला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भारत को समुद्री व्यापार में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह आर्थिक परियोजना होने के साथ चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता के सामने भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने वाला कदम है।

क्या कांग्रेस को दिखाई नहीं देता कि भारत के पड़ोसी देश अपनी सामरिक शक्ति एवं अन्य शक्तियां बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार अपने बंदरगाह नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, तब भारत यदि अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाता है, तो कांग्रेस को इसमें समस्या क्यों दिखाई देती है? कांग्रेस का कहना है कि केवल आईएनएस बाज या अन्य सैन्य परिसंपत्तियों के विस्तार से काम चल सकता है। लेकिन क्या भारत जैसे विशाल और उभरते हुए राष्ट्र को केवल 'काम चलाने' वाली मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए? उम्मीद से अधिक नहीं, किंतु यह तो कांग्रेस समझ ही सकती है? कि 150 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। यदि भारत को वैश्विक व्यापार, नौसैनिक शक्ति और समुद्री रणनीति में अग्रणी बनना है, तो उसे विश्वस्तरीय बंदरगाह, एयरपोर्ट और आधुनिक शहरी ढांचे की आवश्यकता होगी। कांग्रेस शायद यह भूल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सैन्य अड्डों के साथ ही मजबूत आर्थिक और लॉजिस्टिक क्षमता से भी सुनिश्चित होती है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप, ये सभी मिलकर भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे।

कांग्रेस लगातार यह प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि इस परियोजना से बड़े स्तर पर पर्यावरण को नुकसान होगा, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न है।यह परियोजना ईआईए अधिसूचना 2006 और आईसीआरजेड अधिसूचना 2019 के तहत सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त कर चुकी है। इसके लिए विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन किया गया है, जिसमें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय विज्ञान संस्थान, वन्यजीव संस्थान और सैकॉन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने अध्ययन किया है। परियोजना के अंतर्गत 42 अनिवार्य पर्यावरणीय शर्तें लागू की गई हैं। द्वीप के केवल 1.82 प्रतिशत वन क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा और इसके बदले 97.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, 65.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित रखा जाएगा, जहां एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। क्या कांग्रेस यह बताना चाहेगी कि उसके शासनकाल में बनी परियोजनाओं में इतने व्यापक पर्यावरणीय सुरक्षा प्रावधान कितनी बार देखने को मिले थे? कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि परियोजना से शोंपेन और निकोबारी समुदाय प्रभावित होंगे, किंतु सही तथ्य यह है कि परियोजना में किसी भी जनजातीय समुदाय के विस्थापन का प्रस्ताव नहीं है। परियोजना के अंतर्गत जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। 73.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डी-नोटिफाई करने के बदले 76.98 वर्ग किलोमीटर नई भूमि को पुनः जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। यानी कुल आरक्षित क्षेत्र में वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय हितों की निगरानी के लिए स्वतंत्र समितियां गठित की गई हैं और जनजातीय कार्य मंत्रालय, एएजेवीएस तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसे संस्थानों से विस्तृत परामर्श किया गया है। यदि वास्तव में सरकार आदिवासी विरोधी होती, तब क्या इतनी संवेदनशील और निगरानी आधारित व्यवस्था तैयार की जाती? आज विश्व तेजी से बदल रहा है। समुद्री व्यापार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और सामरिक समुद्री मार्ग आने वाले दशकों की शक्ति का निर्धारण करेंगे। भारत यदि इस दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, न कि राजनीतिक विरोध। मोदी सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि भारत को आत्मनिर्भर, सामरिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना है। कहना होगा कि ग्रेट निकोबार परियोजना उसी दृष्टि का हिस्सा है।

वस्तुतः आज ग्रेट निकोबार परियोजना यह सिद्ध करती है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मूल्यांकन और चरणबद्ध विकास के माध्यम से दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। गैस और सौर ऊर्जा आधारित हाइब्रिड पावर प्लांट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन ढांचा और जैव विविधता संरक्षण उपाय यह दर्शाते हैं कि सरकार दीर्घकालिक सतत विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में कहना यही होगा कि ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के भविष्य की परियोजना है। यह सिर्फ एक बंदरगाह या एयरपोर्ट का निर्माण नहीं, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शक्ति, प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कांग्रेस यदि वास्तव में राष्ट्रहित की राजनीति करना चाहती है, तो उसे हर राष्ट्रीय परियोजना का अंधा विरोध बंद कर देना चाहिए। ध्यान रहे- आलोचना होनी चाहिए, सुझाव भी दिए जाने चाहिए, पर विकास को रोकने और देश को कमजोर करने वाली मानसिकता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। भारत अब 20वीं सदी की सोच से आगे निकल चुका है। यह नया भारत है, जो पर्यावरण का संरक्षण भी करना जानता है, आदिवासी हितों का सम्मान भी करता है और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता भी देता है। अब स्वभाविक है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इसी नए भारत की महत्वाकांक्षा, क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जिसे हर हाल में पूरा होना ही चाहिए, इसी में हम सभी भारतीयों का हित निहित है।

बस नाइंटी परसेंट

कटाक्ष

- शशांक दुबे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मई का तीसरा सप्ताह हम हिंदुस्तानियों के लिए लू-लपट और पानी की किल्लत के साथ-साथ तनाव, डांट-डपट, छींटा-कशी और गहरी साँसे छोड़ने के कई कई मंजर लेकर आता है। आखिर इन दिनों सीबीएसई का रिज़ल्ट जो आता है। ना-ना, पास-फैल की चिंता किसी को नहीं, पास तो इन परीक्षाओं में नब्बे फीसदी बच्चे हो जाते हैं। अब ये कोई साठ का दशक तो है नहीं कि नायक अपने ढीले पैंट की जेब से दस का सिक्का निकालकर अखबार खरीदे और रिज़ल्ट में अपना रोल नंबर देख खुशी से साइकल दन्नाते हुए घर चला आए और बरामदे में ही साइकल पटककर 'माँ-माँ मैं इम्तिहान में पास हो गया हूँ' कहते हुए घर में घुसे। अब तो परीक्षा में पास होना वैसा ही है जैसे मेजबान के घर वाई-फ़ाई मिलना या क्रिकेटरों का गुस्सा होना या फ़िल्मी हस्तियों का दूसरी-तीसरी शादी करना। डिवीज़न भी बेमानी है। थर्ड क्लास से तो कोई पास होता नहीं और सेकेंड डिवीज़न भी चंद बदनसीबों को ही नसीब होता है। बहुमत तो केवल फर्स्ट क्लास वालों का होता है और असल परेशानी यहीं से शुरू होती है।

जिसे साठ प्रतिशत अंक मिले, उसे इस बात पर डांट पड़ती है कि यदि वह फरवरी मार्च में विश्व कप के चक्कर में नहीं पड़ता तो सत्तर प्रतिशत ले आता। जो बच्चा सत्तर प्रतिशत लाता है, उसकी मम्मी को अपने पति से ताना सुनना पड़ता है, 'अगर तुमने न लगाया होता झिंगालाला, तो आज एटी परसेंट लाया होता अपना लाला'। एटी परसेंट वाले बच्चे के पापा इस अघट का ठीकरा फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के सर फोड़ते हैं। नब्बे परसेंट पाने वालों के पिताजी अँग्रेजी अखबार में से मुंह निकालकर कहते हैं, 'बस नाइंटी परसेंट !! यू कुड हेव डन बैटर'। जो बच्चे नाइंटी फाइव परसेंट से भी ऊपर ले आते हैं, उन्हें भी चैन कहाँ, आराम कहाँ? उन्हें दो ही बातें सुनने को मिलती हैं, एक तो 'आजकल हर कोई नाइंटी फाइव पर्सेंट ला रहा है', दूसरा, 'हम तो तुमको तब मानें जब आईआईटी में सिलेक्ट होकर बताओ।'

इधर घर का माहौल प्रेशर कुकर, उधर अड़ोसी-पड़ोसी, नाते-रिश्तेदार, मिलने-जुलने वाले, सब इससे बेखबर। वे बच्चे को बधाई देने चले आते हैं। मजबूरी में घर का माहौल नए एसी की तरह ठंडा करना पड़ता है। हर आनेवाला अपने-अपने अंदाज़ से मिठाई मांगता है। कुछ लोग चीनी से भी मीठी आवाज़ में मिठाई माँगते हैं, 'भैया मुंह मीठा नहीं कराओगे'? तो कुछ लोग सरकारी अस्पताल के कंपाउंडर की तरह बेरुखी से पेश आते हुए कहेंगे, 'भैया मिठाई कहाँ है?' कुछ लोग पठानी वसूली की तरह मिठाई वसूलते हैं। वे दरवाजे के बाहर से ही दहाड़ते हुए कहते हैं, 'क्या शर्मा, हद कर दी तुमने कंजूसी की, बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो गया और मिठाई का टुकड़ा तक नहीं'। कुछ लोगों का अंदाज पंडितजी से प्रसाद ग्रहण करने की मुद्रा वाला होता है। वे हथेली के ऊपर हथेली रख कहते हैं, 'मिठाई लाओ मिठाई'। कुछ लोग बड़े ओरिजिनल होते हैं। पहले आपसे रिज़ल्ट पूछेंगे, जब आप बताएँगे तो कहेंगे, 'मैंने कुछ सुना ही नहीं, पहले मिठाई'। बेचारा बच्चा! पापा की खटारा उठाकर बाज़ार से मिठाई लाता है, इसे माँ के हवाले करता है। फिर सेलफोन ऑफ कर, अपनी गर्दन झुका किसी नई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी टेबल तक पहुँच जाता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पल्टीबाजी बना राष्ट्रीय खेल

व्यंग्य

चेतनादित्य आलोक

लेखक पत्रकार हैं।

पंजाब में खेली गयी 'नाम आदमी' दल की हालिया प्रतिस्पर्द्धा ने खासी सुर्खियां बटोरीं। एक ही बार में सात-सात चैंपियन निकले। जरा सोचिए, कितना लंबा अभ्यास किया होगा इन खिलाड़ियों ने। कितनी तकनीकों और टैक्टिक्सों का प्रशिक्षण लिया होगा और कैसे-कैसे गुरु मंत्र दिये होंगे 'भ्रामक जन पलटीबाजी' दल के पेशेवर प्रशिक्षकों ने। यह सब कुछ अंधेरे में ही किया गया होगा। अन्यथा, दूसरे पलटीबाजी दलों को यदि पहले ही पता लग जाता तो इतनी बड़ी सफलता मिलनी मुश्किल थी। हालांकि, उक्त प्रतिस्पर्द्धा के प्रमुख प्रशिक्षकों में से एक ने माना है कि इन्हें ज्यादा प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहले से ही बने-बनाये चैंपियन थे। बस, इनको एक सही दिशा देने भर की जरूरत थी। उनके अनुसार, ये खिलाड़ी एक लंबी छलांग के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

हमारा देश खेलों में अब खूब तरक्की करने लगा है। लोकल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं तक में हमारे खिलाड़ी अपने कौशल का रंगजमाने लगे हैं। हालांकि, दुःख की बात भी है कि अब तक हम किसी भी खेल मेंनंबर वन नहीं बन पाये हैं, लेकिन शायद हमारे दुःख के दिन जल्दी ही समाप्तहोने वाले हैं, क्योंकि जितनी तेजी से हमारा देश 'पल्टीबाजी' के खेल मेंनित्य नयी ऊंचाई हासिल करता जा रहा है, उससे प्रतीत होता है कि हम शीघ्र ही इस खेल में दुनिया में नंबर वन होंगे। इसको लेकर मेरे पुख्ता विश्वास के दो कारण हैं, पहला, कि हम इसे परंपरा से खेलते आ रहे हैं। इस पर हमारीबहुत अच्छी पकड़ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आजादी के कुछ वर्षों के भीतर ही हमने इसको अपना लिया था। तभी से देश में इसके चैंपियन होते रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि अब तक इसका प्रचार-प्रसार अन्य देशों में नहीं हुआ है। जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के बाद जब तक अन्य देश इसे खेलना सीखेंगे, तब तक हमारे खिलाड़ी साल-दर-साल चैंपियन बनते रहेंगे। बहरहाल, इसे राष्ट्रीय खेल घोषित करके हमारे देश ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है।

देश में पल्टीबाजी के विकास की बात करें तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोआ और राजस्थान अब तक इसमें अव्वल आ चुके हैं। पंजाब में खेली गयी 'नाम आदमी' दल की हालिया प्रतिस्पर्द्धा ने खासी सुर्खियां बटोरीं। एक ही बार में सात-सात चैंपियन निकले। जरा सोचिए, कितना लंबा अभ्यास किया होगा इन खिलाड़ियों ने। कितनी तकनीकों और टैक्टिक्सों का प्रशिक्षण लिया होगा और कैसे-कैसे गुरु मंत्र दिये होंगे 'भ्रामक जन पलटीबाजी' दल के पेशेवर प्रशिक्षकों ने। यह सब कुछ अंधेरे में ही किया गया होगा। अन्यथा, दूसरे पलटीबाजी दलों को यदि पहले ही पता लग जाता तो इतनी बड़ी सफलता मिलनी मुश्किल थी। हालांकि, उक्त प्रतिस्पर्द्धा के प्रमुख प्रशिक्षकों में से एक ने माना है कि इन्हें ज्यादा प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहले से ही बने-बनाये चैंपियन थे। बस, इनको एक सही दिशा देने भर की जरूरत थी। उनके अनुसार, ये खिलाड़ी एक लंबी छलांग के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

अब, जबकि एक ही बार में एक ही दल के सात-सात चैंपियन घोषित किये जा चुके हैं, तब 'नाम आदमी' तथा अन्य पलटीबाजी दलों के खिलाड़ी 'भ्रामक जन पलटीबाजी' दल के प्रमुख प्रशिक्षकों और उनके द्वारा घोषित चैंपियनों पर पक्षपात, धोखेबाजी और बेइमानी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल, उनके दिल में अपनी असफलता से अधिक 'भ्रामक जन पलटीबाजी' दल की सफलता की टीस चुभ रही है। वैसे, बेहतर तो यही होता कि किसी की बुराई करने या चिढ़ने-जलने के बदले स्वयं दूसरों से ज्यादा मेहनत की जाती। दूसरों की रेखा काटने के बदले, अपनी रेखा को अधिक लंबी की जाती, जैसा कि 'भ्रामक जन पलटीबाजी' दल के प्रधान खिलाड़ी ने एक बार कहा भी था। वैसे, 'नाम आदमी' तथा अन्य पलटीबाजी दलों का एक आरोप मुझे सही लगता है कि 'राष्ट्रीय पल्टीबाजी विकास और नियंत्रण बोर्ड' की कमान 'भ्रामक जन पलटीबाजी' दल के पास होने के कारण उसके खिलाड़ी इस खेल में लगातार अव्वल हो रहे हैं, लेकिन इसे भी कोई नकार नहीं सकता कि 'इंडियन नेशनल क्लब ऑफ कोर पल्टीबाजी' दल के खिलाड़ी पांच दशकों से ज्यादा समय तक लगातार इस खेल के चैंपियन एवं प्रमुख प्रशिक्षक भी रहे हैं।

संकल्प

गौरव अस्वस्थी

कूदोपाली : पथरीली जमीन पर 'शिक्षा के फूल'

हलधर नाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें अपनी समस्त कविताएं और महाकाव्य कंठस्थ हैं। उन्होंने 22 से अधिक महाकाव्य और खंडकाव्य रचे हैं, जिनका हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उस समय उनकी सादगी और अभावों से भरे जीवन की चर्चा पूरे देश में हुई थी। कहा जाता है कि दिल्ली जाकर सम्मान ग्रहण करने के लिए उन्होंने प्रारंभ में यह कहकर असमर्थता जताई थी कि उनके पास यात्रा का खर्च नहीं है। लेकिन जीवनभर अभावों से जूझने वाले इसी लोककवि ने यह तय किया कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देंगे। इसी संकल्प से वर्ष 2009 में कूदोपाली गांव में 'पद्मश्री लोककवि हलधर नाग आवासीय वन विद्यालय' की शुरुआत हुई। शुरुआत बेहद साधारण थी। स्कूल के नाम पर केवल घास-फूस की मड़ैया थी और छात्र संख्या महज 17।

ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों के बीच बसे बरगढ़ जिले के अंतिम गांव कूदोपाली में शिक्षा की एक ऐसी कहानी आकार ले रही है, जिसे आधुनिक समय का 'नया शांतिनिकेतन' कहा जा सकता है। यह कहानी केवल एक स्कूल की नहीं, बल्कि उस संकल्प की है जिसमें एक लोककवि ने अपने संघर्षों से उपजी संवेदना को गरीब, अनाथ और आदिवासी बच्चों के भविष्य से जोड़ दिया।

कोसली भाषा के प्रसिद्ध लोककवि और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत हलधर नाग ने यहां 'पद्मश्री लोककवि हलधर नाग आवासीय वन विद्यालय' की स्थापना की है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह प्रकृति की गोद में शांतिनिकेतन बसाया था, उसी तरह हलधर नाग ने गांव की डूगरी यानी पथरीली जमीन पर शिक्षा का यह आश्रम खड़ा किया। जंगलों के बीच खड़ी यह इमारतें आज उन बच्चों के सपनों का आधार बन चुकी हैं, जिनके लिए कभी शिक्षा एक दूर की चीज थी।

बरगढ़ जिले के घेंस गांव में जन्मे हलधर नाग का जीवन स्वयं संघर्षों से भरा रहा है। बेहद साधारण परिवार में जन्मे नागजी ने गरीबी को बहुत करीब से देखा। परिवार चलाने के लिए उन्होंने स्कूल में रसोइए का काम किया, स्टेशनरी की छोटी दुकान चलाई और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया। पांचवीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले इस लोककवि ने अपनी प्रतिभा और संवेदनशीलता के बल पर साहित्य जगत में अलग पहचान बनाई। उनकी पहली कविता 'ढाड़ो बरगछ' यानी 'बूढ़ा बरगद' थी। प्रकृति, लोकजीवन और मानवीय संवेदनाओं पर केंद्रित उनकी कविताओं ने उन्हें पश्चिमी ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान बना दिया।

हलधर नाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें अपनी समस्त कविताएं और महाकाव्य कंठस्थ हैं। उन्होंने 22 से अधिक महाकाव्य और खंडकाव्य रचे हैं, जिनका हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उस समय उनकी सादगी और अभावों से भरे जीवन की चर्चा पूरे देश में हुई थी। कहा जाता है कि दिल्ली जाकर सम्मान ग्रहण करने के लिए उन्होंने प्रारंभ में यह कहकर असमर्थता जताई थी कि उनके पास यात्रा का खर्च नहीं है।

लेकिन जीवनभर अभावों से जूझने वाले इसी लोककवि ने यह तय किया कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देंगे। इसी संकल्प से वर्ष 2009 में कूदोपाली गांव में 'पद्मश्री लोककवि हलधर नाग आवासीय वन विद्यालय' की शुरुआत हुई। शुरुआत बेहद साधारण थी। स्कूल के नाम पर केवल घास-फूस की मड़ैया थी और छात्र संख्या महज 17।

विद्यालय की स्थापना में गांव के महेंद्र कुमार ने ढाई एकड़ जमीन दान में दी। उनके बेटे जनक कुमार ने विद्यालय की देखरेख का दायित्व अपने ऊपर लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की सेवा को समर्पित कर दिया। विवाह न करने के सवाल पर जनक कुमार सहजता से कहते हैं–'ये सारे बच्चे ही हमारे परिवार हैं।'

आज यह विद्यालय 125 से अधिक बच्चों की शिक्षा का केंद्र बन चुका है। यहां पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब, अनाथ और आदिवासी परिवारों से आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता मजदूरी करते हैं या जिनके परिवार शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। जंगलों के बीच स्थित यह विद्यालय उनके लिए आशा का केंद्र बन गया है।

विद्यालय की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यहां शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है। बच्चों को श्रम, अनुशासन, सेवा और सामूहिक जीवन का संस्कार भी दिया जाता है। अवकाश के दिनों में बच्चों ने स्वयं श्रमदान कर खेल मैदान समतल किया। वे विद्यालय परिसर में सब्जियां और अन्य फसलें उगाने में भी सहयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन तैयार करने और परोसने में भी बच्चे सहभागी बनते हैं।

भ्रमण के दौरान विद्यालय में अवकाश था, लेकिन 10-12 बच्चे छुट्टियों में भी वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोई सेना में जाना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है और कोई बैंक मैनेजर। बच्चों की आंखों में सपनों की चमक साफ दिखाई देती है।

विद्यालय में पढ़ाने के लिए आसपास के शिक्षक निःशुल्क अपना योगदान देते हैं। चंदन नायक, मर्कंडा बरिहा, रूपेश साहू, लक्ष्मीधर भुए, कल्याण गहिर, मनोज कुशल, बबलू कालेत और मोहन बरिहा जैसे शिक्षक नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद इन शिक्षकों की प्रतिबद्धता विद्यालय की सबसे बड़ी ताकत है।

समय के साथ इस विद्यालय को समाज का सहयोग भी मिलने लगा। हलधर नाग विभिन्न आयोजनों में मिलने वाली सम्मान राशि और अपनी पुस्तकों की रॉयल्टी का अधिकांश हिस्सा विद्यालय पर खर्च करते हैं। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद कई संस्थाएं, समाजसेवी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी इस प्रयास से जुड़ गईं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण में सहयोग दिया। राज्यसभा सदस्य निरंजन बीसी ने अपनी सांसद निधि से पानी की टंकी, सोलर लाइट, बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई। ग्राम पंचायत ने बाउंड्रीवाल बनवाकर जंगली जानवरों के खतरे को कम किया।

विद्यालय परिसर में अब पक्के कक्ष बन चुके हैं और कुछ नए कक्ष निर्माणाधीन हैं। बरामदों की दीवारों पर देश और ओडिशा के महापुरुषों के चित्र लगे हैं, जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। हालांकि संसाधनों की कमी आज भी दिखाई देती है। विद्यालय की रसोई में भोजन अब भी जंगल से लाई गई लकड़ियों के चूल्हे पर पकता है। जनक कुमार बताते हैं कि गैस पर भोजन बनाना विद्यालय के लिए महंगा पड़ता है।

विद्यालय के पूर्व छात्र आज उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। मजदूर पिता की आदिवासी बेटी मिली भोई, जिसने बचपन में ही मां को खो दिया था, आज भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कीट्स संस्थान से बीटेक कर रही है। इसी विद्यालय के छात्र मोहन बरिहा बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि जंगलों के बीच शुरू हुई यह छोटी पहल अब बच्चों के जीवन में बड़े परिवर्तन का माध्यम बन रही है।

विद्यालय को प्रवासी ओडिया परिवारों और स्थानीय समाज का भी सहयोग मिल रहा है। अमेरिका में रह रहे बालकृष्ण दीक्षित और उनका परिवार विद्यालय के निर्माण और मासिक खर्च में मदद कर रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मण साहू ने भी यहां कक्ष निर्माण में सहयोग दिया है। आसपास के ग्रामीण मध्याह्न भोजन के लिए अपनी फसल दान में दे जाते हैं।

हलधर नाग जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और उनकी प्रिय कविता 'ई माटी पावन पोरे' सामूहिक स्वर में गाने लगते हैं। कुछ देर के लिए पूरा परिसर साहित्यिक और भावनात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लोककवि बच्चों को कविता सुनाने के साथ-साथ अच्छा इंसान बनने की सीख भी देते हैं।

कूदोपाली का यह वन विद्यालय बताता है कि शिक्षा केवल भवनों और संसाधनों से नहीं चलती, बल्कि संवेदना, समर्पण और सामाजिक सहभागिता से जीवित रहती है। पथरीली जमीन पर उगे ये 'शिक्षा के फूल' इस बात का प्रमाण हैं कि यदि संकल्प मजबूत हो तो जंगलों के बीच भी सपनों की खेती की जा सकती है।

आज जब शिक्षा तेजी से बाज़ार और प्रतिस्पर्धा के दबाव में बदल रही है, तब कूदोपाली का यह 'नया शांतिनिकेतन' याद दिलाता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य बनाना है। हलधर नाग का यह प्रयास केवल विद्यालय निर्माण नहीं, बल्कि समाज के सबसे वंचित बच्चों के भविष्य को रोशन करने का आंदोलन है।

सामयिक

राज कुमार सिन्हा

लेखक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं।

भारत के शहर क्यों बन रहे हैं आग के गोले?

प्रशांत महासागर में विकसित होने वाली जलवायु घटना अल नीनो के कारण वैश्विक तापमान सामान्य से अधिक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बनने वाले अल नीनो वैश्विक तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है। पहले अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र था, लेकिन अब मानवजनित जलवायु परिवर्तन इसकी तीव्रता बढ़ा रहा है। समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं और चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ रही हैं। हीटवेव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वैश्विक गर्मी है। जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में जाती हैं।

एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी इस समय अतिरिक्त 1.9 डिग्री गर्म होने की ओर है जो पेरिस समझौते के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल से जुड़े जलवायु वैज्ञानिकों की एक टीम ने शोध-पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत का औसत तापमान पिछले एक दशक (2015-2024) में लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो 20वीं सदी की शुरुआत (1901-1930) की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में वर्ष के सबसे गर्म दिन का तापमान 1950 के दशक से अब तक 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है।

बढ़ती गर्मी और लगातार पड़ रही हीटवेव के कारण शहर के निवासियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, जिसका सबसे अधिक असर श्रमिकों और कमजोर समुदायों पर पड़ रहा है। दुनिया की 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में 95 नाम भारत के शहर का है। शहर में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों और जंगलों की कटाई के कारण प्राकृतिक ठंडक गायब हो गई है। शहर के तालाबों को बिल्डर भरकर मकान बना कर बेच रहे हैं। शहरों में कांक्रीट और डामर की सड़कें दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात में छोड़ती हैं, जिससे शहर गांवों की तुलना में ज्यादा गर्म रहते हैं। वाहनों, उद्योगों और एयर कंडीशनर (एसी) के अत्यधिक उपयोग से भारी मात्रा में कृत्रिम गर्मी निकलती है, जो शहरों के तापमान को बढ़ाती है।राजधानी भोपाल में ग्रीन कवर घटने की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट व आईआईएससी बेंगलुरु के रिपोर्ट के अनुसार 2009 में 35 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल था। जो 2019 में महज 9 प्रतिशत रह गया। 2030 तक 3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

हमलोग पेड़ काटकर हाईवे बनाने और जंगल उजाड़कर खदानें खोलने में लगे हैं, तो नतीजे आज हम भुगत रहे हैं। भारत आज एक 'हीट चैंबर' बन चुका है, और इसकी जवाबदेही मौसम पर डालकर जिम्मेदार बच निकलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, भारत चरम मौसम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के मामले में पांचवां सबसे अधिक संवेदनशील देश है। एक वैश्विक समीक्षा 2017 में कहा गया है कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि का वर्तमान रुझान जारी रहता है, तो सदी के अंत तक गर्मी और आर्द्रता के बढ़ते स्तर के कारण छह घंटे या उससे अधिक समय तक सीधे धूप और धूप के संपर्क में रहने वाले लोगों का जीवित रहना असंभव हो सकता है। सी- 40 विश्व के 96 देशों का एक संगठन है, जो शहरों का जलवायु के संबंध में नेतृत्व करता है। इसके सर्वेक्षण के अनुसार इस समय दुनिया के 350 से ज्यादा शहर अत्यधिक गर्मी से प्रभावित हैं। सन् 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर 970 हो जाएगी।

प्रशांत महासागर में विकसित होने वाली जलवायु घटना अल नीनो के कारण वैश्विक तापमान सामान्य से अधिक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बनने वाले अल नीनो वैश्विक तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है। पहले अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र था, लेकिन अब मानवजनित जलवायु परिवर्तन इसकी तीव्रता बढ़ा रहा है। समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं और चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ रही हैं। हीटवेव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वैश्विक गर्मी है। जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में जाती हैं। ये गैसें गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। भारत में पिछले चार दशकों में लू की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है, जिससे कई क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव अधिक हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन क्रियान्वयन योजना 2023-28 तैयार की है, जिसमें 97,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। लेकिन पर्यावरण विभाग का बजट मात्र 31 करोड़ रुपये है। जबकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2022 से 2025 तक मध्यप्रदेश ने 598 दिनों में गंभीर मौसम का सामना किया है और इस दौरान 1,439 लोगों की मौतें हुई है। सरकार जलवायु संकट की गंभीरता को प्राथमिकता नहीं दे रही है। जबकि पूरी दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए निवेश बढ़ा रही है, तब मध्यप्रदेश सरकार को ठोस कार्ययोजना बनाने का प्रयास करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का नहीं, बल्कि वर्तमान का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। भारत के शहर तेजी से 'हीट चैंबर' में बदल रहे हैं, जहां कांक्रीट, अंधाधुंध निर्माण, जंगलों की कटाई, तालाबों के विनाश और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर विकास मॉडल ने प्राकृतिक संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीबों, श्रमिकों, बुजुर्गों और कमजोर समुदायों पर पड़ रहा है, जिनके पास बढ़ती गर्मी से बचने के संसाधन नहीं हैं।

भोपाल जैसे शहरों में घटता ग्रीन कवर और बढ़ते तापमान इस बात का संकेत हैं कि यदि विकास की वर्तमान दिशा नहीं बदली गई, तो आने वाले वर्षों में जीवन और आजीविका दोनों पर गंभीर खतरा पैदा होगा। सरकारें जलवायु संकट को केवल मौसम की असामान्य घटना बताकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकतीं। जब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में अत्यधिक गर्मी मानव जीवन के लिए असहनीय हो सकती है, तब केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है; उनके लिए ठोस बजट, राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी आवश्यक है। आज जरूरत है कि विकास की परिभाषा को बदला जाए, पेड़ों, जलाशयों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाए बिना कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। यदि अभी भी सरकारें, उद्योग और समाज नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे भारत का सामना करना पड़ेगा, जहां गर्मी केवल असुविधा नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट बन जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

सिर्फ पेय नहीं, दुनिया की धड़कन है चाय

चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक संवाद है और दुनिया के करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। दुनियाभर में पानी के बाद यदि कोई पेय पदार्थ सबसे ज्यादा पसंद और उपभोग किया जाता है तो वह है चाय। सुबह की पहली किरण के साथ नींद को अलविदा कहने से लेकर, दफ्तर की थकान मिटाने और मेहमानों के स्वागत तक, चाय हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुकी है। इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 21 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम 'चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना' न केवल चाय के पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पर जोर देती है बल्कि उन लाखों छोटे किसानों और श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने का भी आह्वान करती है, जिनकी आजीविका इस उद्योग से जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का इतिहास बेहद दिलचस्प है। कुछ साल पहले तक दुनियाभर के चाय उत्पादक देशों में यह दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था। इसकी शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2005 में भारत की राजधानी नई दिल्ली से हुई थी। इसके बाद श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों ने मिलकर इसे मनाना शुरू किया। हालांकि, तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। चाय को वैश्विक मंच पर उसका वास्तविक हक दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी और दूरदर्शी पहल की। वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। भारत के प्रस्ताव पर गहन विचार करने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2019 को एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया और 21 मई को आधिकारिक रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस' घोषित कर दिया।

तब से लेकर आज तक, हर साल 21 मई को यह दिवस वैश्विक स्तर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाया जाता है। मई का महीना इसलिए भी चुना गया क्योंकि इस समय अधिकांश प्रमुख चाय उत्पादक देशों में उत्तम गुणवत्ता वाली चाय की फसल तैयार होती है। चाय की खेती बहुत ही विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिक परिस्थितियों में होती है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव और अनिश्चित वर्षा ने चाय बागानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में 'चाय को बनाए रखना' का अर्थ है, पर्यावरण-अनुकूल खेती यानी कीटनाशकों के सीमित उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा यानी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना तथा पारदर्शी मूल्य श्रृंखला यानी खेत से लेकर कप तक एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाना, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। चाय क्षेत्रवैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का उद्योग है लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी वे छोटे किसान और मजदूर हैं, जो दिन-रात बागानों में पसीना बहाते हैं। दुनियाभर में 1.3 करोड़ से अधिक लोग, जिनमें छोटे किसान और उनके परिवार

शामिल हैं, आजीविका के लिए चाय पर निर्भर हैं। इस वर्ष की थीम इन छोटेउत्पादकों के व्यवसाय मॉडल को मजबूत करने पर केंद्रित है। चाय के पत्तों को चुनने से लेकर उनके प्रसंस्करण तक में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। यह उद्योग महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करता है। विकासशील और सबसे कम विकसित देशों में चाय का निर्यात खाद्य आयात बिलों के वित्तपोषण में मदद करता है, जिससे वहां की

अर्थव्यवस्थाओं को सहारा मिलता है।चाय का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन चीन में हुई थी, जहां इसका उपयोग शुरू में एक औषधीय पेय के रूप में किया जाता था। धीरे-धीरे यह चीन की सीमाओं को पार कर जापान, यूरोप और फिर औपनिवेशिक काल में भारत और दुनिया के अन्य कोनों तक पहुंची। आज, इतनी सहस्राब्दियों के बाद भी स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका योगदान उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। यदि वैश्विक स्तर पर चाय के आंकड़ों पर नजर डालें, तो परिदृश्य अत्यंत रोचक है। दुनिया में सबसे अधिक चाय उत्पादन चीन में होता है जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एशिया महाद्वीप आज भी विश्व चाय उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। उपभोग के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, जहां चाय केवल पेय नहीं बल्कि सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर उत्पादित कुल चाय का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा उन्हीं देशों में उपभोग कर लिया जाता है, जहां इसका उत्पादन होता है। चाय उद्योग से 13 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, जिनमें छोटे किसान और उनके परिवार प्रमुख हैं। भारत में उत्पादित चाय का लगभग 30 प्रतिशत घरेलू बाजार में ही खप जाता है। यहां चाय हर सुबह की ऊर्जा, रिश्तों की गर्माहट और जीवन के हर सुख-दुख की स्थायी साथी मानी जाती है। भारतीयों और चाय का रिश्ता अनूठा है। कुछ लोग इसे महज एक लत कह सकते हैं लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में यह 'जिंदगी की खुराक' और आतिथ्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। अमीर का बंगला हो या गरीब की झोपड़ी, घर आए मेहमान का स्वागत बिना चाय के अधूरा माना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (जैसे असम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र) में विस्तृत चाय के बागान न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं बल्कि लाखों परिवारों के जीवन का आधार भी हैं। चाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर व्यक्ति के स्वाद और मिजाज के अनुरूप खुद को ढाल लेती है। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में इसे बनाने के तरीकों में गजब की भिन्नताएं हैं। दूध, चीनी और चायपत्ती को पानी के साथ अच्छी तरह उबालकर, उसमें अदरक, इलाइची, लौंग और काली मिर्च डालकर बनाई जाने वाली कड़क चाय अधिकांश भारतीयों की पहली पसंद है। कोरोना महामारी के दौर के बाद से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जो लोग पहले चाय नहीं पीते थे, वे भी अब काढ़े या इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अदरक और मसालों वाली चाय का सेवन करने लगे हैं। वजन नियंत्रित रखने और एंटीऑक्सीडेंट्स का लाभ उठाने के लिए आधुनिक जीवनशैली में ग्रीन टी और ब्लैक टी का चलन तेजी से बढ़ा है।

चाय दुनिया का सबसे पुराना और पानी के बाद सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। जब हम अपने कप से चाय की एक चुस्की लेते हैं तो उसके पीछे किसी चाय बागान मजदूर के हाथों की मेहनत, किसी छोटे किसान की उम्मीदें और प्रकृति का अनमोल योगदान छुपा होता है। ब्रिटेन में 'आफ्टरनून टी', जापानमें 'टी सेरेमनी' और भारत में 'टपरी की चाय' इसके गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती हैं। सभी प्रकार की चाय (ब्लैक, ग्रीन, ओलोंग, व्हाइट) मुख्य रूप से एक ही पौधे कैमेलिया साइनेंसिस से आती हैं।इनका स्वाद और रंग इनके ऑक्सीकरण और किण्वन की तकनीक के आधार पर बदल जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दुनिया के छह चाय खेती स्थलों को 'विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली' घोषित किया गया है। इनमें से 4 चीन में, 1 जापान में और 1 दक्षिण कोरिया मेंस्थित है। प्रमुख उत्पादक देशों में कुल खपत अधिक होने के बावजूद प्रतिव्यक्ति खपत अभी भी कई पश्चिमी देशों की तुलना में कम है, जो यह दर्शाता है कि इस उद्योग में आगे बढ़ने की अभी अपार संभावनाएं हैं।

भविष्य मालिका पुराण अत्यंत गुप्त ग्रंथ, पंडित डॉ. काशीनाथ मिश्र उड़ीसा

भोपाल। जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान पंडित डॉ.काशीनाथ मिश्र ने भगवान् के नित्य पंच सखा में से एक सखाअच्युतानंद द्वारा 6 सौ साल पूर्व रचित अत्यंत गुप्त ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण के अंशों के आधार पर 2032 से सत्य युग की शुरुआत होने का दावा अपनी भविष्य मालिका पुराण पार्ट एक के अंश में लिखा है कि जब विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों महापरिवर्तन के आगमन को महसूस कर रहे होते हैं, तब भी मानवता के पास इस संकट से उबरने का कोई निश्चित ओर सार्वभौमिक समाधान नहीं होता। ऐसे समय में केवल 'भविष्य मलिका' ही दिव्या मार्ग प्रदान करती है ,जो संपूर्ण मानव सभ्यता की रक्षा करने में सक्षम है। इस शास्त्र का मूल सिद्धांत है पापपूर्ण कर्मों का त्याग करें, और जीवन की रक्षा हेतु सभी धर्म के लोगों को 'त्रिकाल संध्या धारा' (त्रिसंध्या संध्या) को अपना चाहिए। जीवन में सत्य, शांति, दया ,क्षमा और मित्रता जैसे गुणों को अपनाएं। युग परिवर्तन के इस समय में जीवन की रक्षा के लिए यह गुप्त तत्व ही एकमात्र मृत्यु संजीवनी है। ज्ञातव्य है कि आपने 'श्री जगन्नाथ चेतना एवं संस्कृति जागरण' संस्थान के माध्यम से वे निरंतर कथा व अनुष्ठान करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा): कांगड़ा के प्रागपुर (ज्वाला जी, वेदव्यास परिसर) में भव्य पंच-रात्रि जगन्नाथ अनुष्ठान का आयोजन एवं नेतृत्व किया था। वहीं राजस्थान (उदयपुर): उदयपुर की पावन भूमि पर उन्होंने अत्यधिक प्रचंड तापमान (40एसी से अधिक) के बीच भव्य दिव्य कल्कि कथा का सफल आयोजन किया था। वैश्विक (अंतरराष्ट्रीय) प्रचार एवं डिजिटल माध्यम से भविष्य मालिका एवं जगन्नाथ संस्कृति की कथाएँ भौगोलिक सीमाओं को पार कर करके वैश्विक (ग्लोबल) स्तर पर पहुँच चुकी हैं। आप अंतरराष्ट्रीय संगठन भविष्य मालिका इंटरनेशनल (विश्व सनातन धर्म) संगठन की स्थापना की है। जिसके माध्यम से विश्वभर के साधक डॉ काशीनाथ मिश्र जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। वैश्विक डिजिटल सत्संग: वे गूगल मीत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश-विदेश के भक्तों के लिए लाइव ऑनलाइन सत्संग एवं कथा सत्रों का संचालन करते हैं।

भविष्य मालिका एवं जगन्नाथ संस्कृति की कथाएं भौगोलिक सीमाओं को पार कर वैश्विक ग्लोबल स्तर तक पहुंच चुकी है। अंतरराष्ट्रीय संगठन भविष्य मालिका इंटरनेशनल (विश्व सनातन धर्म) संगठन की स्थापना की है। जिसके माध्यम से विश्वभर 1सौ 56 देशों के साधक जुड़े हुए हैं।आप गूगल मीत एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश-विदेश के भक्तों के लिए लाइव ऑनलाइन सत्संग और कथा सत्रों का संचालन करते हैं।बहुभाषी अनुवाद और प्रसार: जगन्नाथ महिमा और भविष्य मालिका के ज्ञान को विश्वभर में पहुँचाने के लिए उनकी पुस्तकों (जैसे च्जगन्नाथ सौरभ संभारज्ञ) का अनुवाद हिंदी, ओड़िया, बांग्ला के साथ-साथ अंग्रेजी, रूसी (रशियन), जापानी भाषा में हैं।

प्रकाश तरण पुष्कर में बच्चों की तबीयत बिगड़ी

भोपाल में स्विमिंग के दौरान सांस लेने में तकलीफ; अस्पताल लेकर दौड़े परिजन

भोपाल (नप्र)। भोपाल के लिंक रोड नंबर-1 स्थित प्रकाश तरण पुष्कर में स्विमिंग के दौरान करीब 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। परिजन बच्चों को तुरंत जेपी हॉस्पिटल लेकर

पहुंचे। स्विमिंग के दौरान 2 बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। हालांकि, अब बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

मामला बुधवार शाम 5 बजे का है। प्रकाश तरण पुष्कर में कई बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन सचिन जैन ने बताया कि उनकी बेटी आध्या जैन (15) भी प्रकाश तरण पुष्कर गई हुई थीं। यहां करीब 20-25 बच्चे थे। जो बच्चे पानी में थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बेटी आध्या समेत दो बच्चों को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। जहां सभी प्राथमिक इलाज किया गया।

सेल्टिया हत्याकांड का इनामी आरोपी पुणे से गिरफ्तार

युवक की हत्या कर शव तालाब में फेंका था, सभी आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। बोरदेही थाना क्षेत्र में हुए चर्चित सेल्टिया जलाशय हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस सनसनीखेज हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। गौरतलब है कि 15 मई 2026 को ग्राम कारोपानी के समीप सेल्टिया जलाशय में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राधेश्याम बट्टी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। युवक का शव पानी में औंधे मुंह पड़ा मिला था, जिसे एक भारी पेड़ के तने के नीचे दबाया गया था। मृतक की पहचान राजू उईके 22 निवासी ढाकरवाड़ी थाना नवेगांव जिला छिंदवाड़ा के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और गंभीर चोटों के कारण हत्या की पुष्टि हुई थी। जांच में सामने आया था कि मजदूरी के पैसों के लेन-देन को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में पता चला था कि 13 मई को एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद राजू उईके आरोपियों के साथ मोटरसाइकिल से गया था, जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा था।

पहले ही चार आरोपियों को किया जा चुका था गिरफ्तार :पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ के आधार पर 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रुपेश कवडे निवासी टुई ढाना सेल्टिया जिला छिंदवाड़ा, आयुष नर्रे निवासी बामला जिला बैतूल, तेजीलाल उईके निवासी ढाकरवाड़ी जिला छिंदवाड़ा और एक विधि-विरुद्ध बालक शामिल थे। वहीं फरार आरोपी संजय उर्फ संजू पिता अनिल धुर्वे उम्र 20 वर्ष निवासी ढाकरवाड़ी थाना नवेगांव जिला छिंदवाड़ा पर पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने लगातार तलाश के बाद आरोपी संजय उर्फ संजू को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। थाना बोरदेही में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

बेटियों की शिक्षा, जनजातीय विकास और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का किया आह्वान

प्रधानमंत्री का संकल्प, 2047 तक कोई भी बच्चा सिकल सेल से प्रभावित न रहे : राज्यपाल

बैतूल। सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी को जागरूकता, समय पर जांच और व्यवस्थित उपचार के माध्यम से नियंत्रित एवं समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि जानकारी के अभाव में यह बीमारी माता-पिता से बच्चों तक पहुंच जाती है, लेकिन समय रहते जांच कराने और स्वास्थ्य सावधानियां अपनाने से इसके प्रसार को रोका जा सकता है। राज्यपाल श्री पटेल बुधवार को भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन-2047 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले दुर्गादास उईके, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद मोहन नागर, विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, विधायक घोड़ाडोंगरी गंगाबाई उईके, सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग मंगल सिंह धुर्वे, आयुक्त नर्मदापुरम श्रीकांत बनोठ, पुलिस महानिरीक्षक मिथलेश कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष जिला पंचायत हंसराज धुर्वे, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि बैतूल जिले में सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यह बीमारी विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों, युवाओं और माताओं को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और उसी दिशा में यह अभियान एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि भीमपुर में स्थापित नई जांच मशीन से अब क्षेत्र के लोगों की शीघ्र जांच हो सकेगी और समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि जिले में सिकल सेल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत अब तक 8 लाख 62 हजार 332 हितग्राहियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जिले में 1681 सिकल सेल डिजीज मरीज तथा 7162 सिकल सेल कैरियर मरीज चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही 24 हजार 993 गर्भवती महिलाओं की भी सिकल सेल जांच की गई है।

उन्होंने सिकल सेल से प्रभावित मरीजों से नियमित उपचार कराने और संतुलित जीवनशैली अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी उपचार उपलब्ध हैं। उन्होंने तैलीय एवं बाहर के भोजन से बचने, पौष्टिक आहार लेने, नियमित व्यायाम करने तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक देश का कोई भी बच्चा सिकल सेल से प्रभावित न रहे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं तथा देशभर में 7 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के माध्यम से सिकल सेल उन्मूलन का आह्वान किया। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों, विशेषकर बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षा ही प्रगति और सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बेटियों को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने दैनिक भोजन में मिलेट्स के उपयोग को भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया।

सिकल सेल उन्मूलन अभियान जन आंदोलन बने : केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया सिकल सेल मिशन-2047 देश को सिकल सेल मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि भीमपुर में सिकल सेल जांच मशीन का लोकार्पण जनजातीय एवं वंचित समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन जागरूकता और जनभागीदारी का अभियान है। गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाकर आने वाली पीढ़ियों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि बैतूल जिले में व्यापक स्तर पर सिकल सेल स्क्रीनिंग कर मरीजों एवं कैरियर की पहचान की गई है, जिससे समय पर उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

हितग्राहियों को वितरित किए हितलाभ, किया संवाद

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भीमपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर उनसे संवाद किया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने लवकेश मोरसे निवासी खुर्दा ग्राम पंचायत बटकी तथा उषा ढिकारे निवासी ग्राम दामजीपुरा, तहसील भीमपुर को सिकल मित्र प्रमाण पत्र प्रदान किए। वहीं रेखा उईके निवासी ग्राम बटकी को यूडीआईडी कार्ड तथा ऋषि झरबड़े निवासी बैतूल को जेनेटिक कार्ड वितरित किया गया। राज्यपाल श्री पटेल ने ग्राम पंचायत डुलारिया निवासी टीबी मरीज दिव्या उईके को फूड बास्केट प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य और नियमित उपचार के लिए प्रेरित किया। महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देते हुए मां गंगा आजीविका स्वयं सहायता समूह, ग्राम भीमपुर की अध्यक्ष रूखमा नर्रे एवं सचिव श्रीमती सरिता नर्रे को 6 लाख रुपये की सीसीएल राशि का चेक वितरित किया गया।

मिशन रानी अभियान का किया शुभारंभ

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम में बैतूल जिले में महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती माताओं में एनीमिया नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए मिशन रानी अभियान का शुभारंभ किया। नोडल अधिकारी सिकलसेल उन्मूलन डॉ अंकिता सीते ने बताया कि मिशन रानी अर्थात् एनीमिया तथा पोषण एवं गैर-पोषण संबंधी समस्याओं में समग्र कमी लाने का अभियान के माध्यम से एनीमिया के कारणों की पहचान कर समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के अंतर्गत केवल आयरन की गोलियों के वितरण तक सीमित न रहकर, एनीमिया के अन्य कारणों जैसे विटामिन बी-12 की कमी, सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया की जांच और उपचार भी सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में बताया गया कि अभियान के तहत हीमोग्लोबिन जांच, संपूर्ण रक्त जांच, सीरम फेरिटिन, विटामिन बी-12 एवं विशेष रक्त परीक्षण किए जाएंगे।

जीवों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, विश्व में परिवर्तन,वायरस, प्राकृतिक आपदा आ चुकी है, जगन्नाथ संस्कृति के विशारद डॉ. मिश्र

हीरालाल गोलानी

भोपाल। जीवों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। उनको मारना पूरे संसार को भारी पड़ेगा। विश्व में परिवर्तन हो रहा है। पूरे विश्व में मानव मनमाने करने पर तुला हुआ है। इसके दुष्प्रभाव पूरी मानव सभ्यता को झकझोर कर रख देंगे। आफ्रीका, यूरोपीयन देशों में जहां ज्यादा जीव हत्या होती है। सीमा पार वायरस, प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दे दी है। बारम्बार भूकम्पों का प्रकोप बना रहेगा। भारत में धर्म एवं अधर्म दोनों की बाहुल्यता विद्यमान है। लेकिन देर सबेर हम भी अछूते नहीं रहेंगे। शास्त्र विधि के अनुसार प्रत्येक ऋतुओं के फल अलग-अलग होते हैं। किन्तु वर्तमान समय में देखने को मिला रहा है कि सभी फल हमें प्राप्त हो रहें हैं। यह घोर कलयुग की पराकाष्ठा है। उक्त उद्गार जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान डॉ पंडित काशीनाथ मिश्र उड़ीसा ने भोपाल गर्ल्स स्कूल पंचवटी परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत पुराण, भविष्य मालिका पुराण कथा के अवसर पर भारी संख्या मातृशक्ति एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कहें। इसके पूर्व आपने जगन्नाथ भगवान् एवं समस्त देवी-देवताओं को प्रणाम करते कथा प्रारंभ की थी।आपने आगे कहा कि प्रकृति से खिलवाड़,मनुष्य की मनमानी के कारण संसार को दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा।यह मिथ्या बिल्कुल न माने। संसार में सूखा पड़ने की पूरी संभावना है। लोगों को खाने का अन्न, पीने को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मनुष्यों में सुन्दरता नहीं बनी रहेगी। मंहगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। जिसके पास धर्म-कर्म होगा ऐसे ही व्यक्ति बचें रहेंगे।ऐसा प्रकोप होगा कि गांव में नहीं के बराबर लोग बचे रह पाएंगे। भारी बरसात, असहनीय गर्मी होगी। 64 प्रकार की बीमारियां पैर फैलाएंगी। दवाईयां काम करना बंद कर देंगी। 49 प्रकार की हवाएं चलने लगेगी। हम यह सब 600 सौ साल प्राचीन ग्रंथ

भविष्य मालिका पुराण के आधार पर विश्वास के साथ कहता हूं। इसी कारण मैं यह सब धर्म एवं प्राणी के लिए जनजागरण अभियान कर रहा हूं।मैं इस मंच से कह रहा हूं कि मैं कथा कि लिए भारत में एवं विदेशी में भी कोई पैसा नहीं लेता हूं। मेरा उद्देश्य मानव सभ्यता के लिए समर्पित है। जब तक सांस में सांस है।तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा। मैं यहां उपस्थित जन जन से आव्हान करता हूं कि अभी भी समय है कि त्रिकाल संध्या का पाठ अवश्य करें। त्रिकाल संध्या करने मात्र से मानव सभ्यता बच पाएंगे। इसमें समय भी नहीं लगता।न ही कोई व्यय लगता है। मृत्यु होने पर धन दौलत सब यहीं रह जाता है। यह ऐसी पूंजी जो मृत्यु के उपरांत भी आत्मा के साथ जाती है। श्रीमद्भागवत कथा पढ़ें,माधव, माधव भजे राम राम भजे। गौ माता की सेवा एवं तुलसी माता की पूजा करें।यह ऐसा अमृत है जो आपकी सुरक्षा करेगा। यह ऐसा टानिक है जो आपकी उम्र बढ़ाएगा।

जगन्नाथ संस्कृति के विशारद श्री मिश्र ने आगे कहा कि भक्त प्रह्लाद एवं उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप की कथा पर अनेकों सारगर्भित उद्बोधन देकर कहा कि भक्त प्रह्लाद भगवान् विष्णु भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप खुद को ही ईश्वर स्वरूप मानता था। जिसमें ब्रह्माजी का वरदान था कि उसके मृत्यु अमुक अमुक से नहीं होगी। लेकिन भक्त प्रह्लाद की भक्ति से जगत के पालनहार भगवान् विष्णु ने अधिक मास उत्पन्न करके नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया।

सतपुड़ा वैली स्कूल के छात्रों ने कैम्ब्रिज परीक्षा में लहराया परचम, जिले को दिलाई वैश्विक पहचान

बैतूल। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन (सीएआईई), यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित मार्च 2026 की कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी एवं प्राइमरी चेकपॉइंट परीक्षा में सतपुड़ा वैली स्कूल, बैतूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। परिणामों ने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को प्रमाणित किया है। कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी चेकपॉइंट में तेजस गोठी ने तीनों विषयों में शानदार प्रदर्शन करते हुए गणित में 43/50, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज में पूर्ण 50/50 तथा विज्ञान में 46/50 अंक प्राप्त किए। वंश राठौर ने गणित में 49/50 अंक हासिल कर सर्वोच्च प्रदर्शन किया। उन्हें इंग्लिश में 38/50 और विज्ञान में 37/50 अंक मिले। सुयश सुमन ने गणित में 46/50 और विज्ञान में 39/50 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं आयुष भील, कनिष्का गोठी, जुमाना हुसैन, अधिराज अतुलकर और मीशा खत्री ने भी सभी विषयों में सराहनीय परिणाम हासिल किए।

ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट छूट के खिलाफ केमिस्टों का हल्लाबोल, धार जिले में 1550 से अधिक मेडिकल स्टोर बंद

धार। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को जिलेभर में दवा कारोबार पूरी तरह ठप रहा। ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा दी जा रही भारी छूट के विरोध में जिले के 1550 से अधिक केमिस्टों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। इस एक दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक साफ देखने को मिला। केमिस्टों के इस आंदोलन को चिकित्सा क्षेत्र से भी समर्थन मिला। विरोध के चलते जिले के निजी नर्सिंग होम की नियमित ओपीडी पूरी तरह बंद रही। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अस्पतालों में इमरजेंसी (आपातकालीन) सेवाएं सुचारू रूप से चालू रखी गईं, जिससे गंभीर मरीजों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

इन प्रमुख मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई : एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. अशोक शास्त्री , सचिव आशीष बांगर ने बताया कि यह आंदोलन छोटे व्यापारियों के अस्तित्व को बचाने के लिए है। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए। कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दवाओं पर दिए जा रहे भारी डिस्काउंट पर नियंत्रण किया जाए। बाजार में नकली दवाओं के अवैध कारोबार पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। जिलाध्यक्ष डॉ. अशोक शास्त्री ने ऑनलाइन दवा व्यापार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि च्ऑनलाइन और बड़े कॉर्पोरेट डिस्काउंट के कारण छोटे और पारंपरिक कारोबारियों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मेडिकल व्यवसाय को खत्म करने की सोची-समझी कोशिश की जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऑनलाइन माध्यमों से इन दिनों बाजार में नींद की दवाइयों (स्लीपिंग पिल्स) का दुरुपयोग बेहद बढ़ गया है, जिसकी गिरफ्त में देश की युवा पीढ़ी आ रही है।ज्ज व्यापारियों ने इस बंद के माध्यम से अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। केमिस्ट एसोसिएशन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संबंधित विभागों ने उनकी मांगों का जल्द ही कोई उचित समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और अधिक उग्र और राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाएगा।

भाजपा के दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का मांडव में शुभारंभ, 7 सत्रों में संगठन और विचारधारा पर हुआ मंथन

भाजपा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए निरंतर कार्य कर रही है: मोघे

धार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी धार के दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का बुधवार को ऐतिहासिक नगरी मांडव में विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन सात अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यपद्धति, सरकार की उपलब्धियां, गरीब कल्याण योजनाएं तथा कार्यकर्ता विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण वर्ग में जिलेभर से बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री कृष्ण मुरारी मोघे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती संभाग प्रशिक्षण प्रभारी दिलीप पटोंदिया, जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी नानूराम कुमावत, जिला संगठन प्रभारी सुभाष कोठारी, धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव तथा पूर्व विधायक वेलसिंह भूरिया मंचासीन थे। शुभारंभ मां सरस्वती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन व वंदेमातरम के साथ हुआ।

भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने संगठन की मजबूती पर जोर देते

हुए कहा कि भाजपा की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और पार्टी को प्रत्येक बूथ पर मजबूत बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को कार्यकर्ताओं के लिए वैचारिक एवं संगठनात्मक रूप से उपयोगी बताया।

भाजपा का संगठन निरंतर प्रशिक्षण और अनुशासन के बल पर आगे बढ़ रहा है :मुख्य वक्ता कृष्ण मुरारी मोघे ने 'हमारा सैद्धान्तिक अधिष्ठान' विषय पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति से घबराई राष्ट्रविरोधी ताकतें देश में सामाजिक एवं आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए निरंतर कार्य कर रही है।

मोघे ने एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा भाजपा की पंचनिष्ठाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प से प्रेरित संगठन है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान का विचार निहित है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारतीयता की आत्मा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र भावना भाजपा की विचारधारा का मूल आधार है। उन्होंने भाजपा की पंचनिष्ठाओं – राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, शोषणमुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, मूल्य आधारित राजनीति तथा आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण को कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बताया।

दूसरे सत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम यादव ने 'विचार परिवार' विषय पर संबोधित किया। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. शरद विजयवर्गीय ने की। यादव ने संगठन की वैचारिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विभिन्न अनुषांगिक संगठनों की भूमिका पर जानकारी दी।

तीसरे सत्र में जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी नानूराम कुमावत ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस सत्र की अध्यक्षता अजजा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रजनीश मालवीय ने की।

चौथे सत्र में संतोष मेहता ने 'कार्य विस्तार' विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने संगठन के विस्तार, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने की।

पांचवें सत्र में खरगोन लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने केंद्र एवं राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इस सत्र की अध्यक्षता भाजपा नेता डॉ प्रह्लाद सिंह सोलंकी ने की।

छठवें सत्र में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 'कार्य पद्धति' विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठनात्मक कार्यशैली, जनसंपर्क और आधुनिक कार्य प्रणाली पर अपने विचार रखे। इस सत्र की अध्यक्षता योगेश अग्रवाल ने की।

प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन के अंतिम एवं सातवें सत्र में विवेक भटोरे ने 'व्यवहारिक विषय' पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने संगठन में व्यवहार, संवाद शैली, जनसंपर्क और कार्यकर्ता जीवन में अनुशासन की महत्ता पर प्रकाश डाला।

संक्षिप्त समाचार

सोनाघाटी में अवैध मुरूम उत्खनन पर 32 लाख 25 हजार का जुर्माना, पोकलेन मशीन राजसात

बैतूल (निप्र)। जिले के सोनाघाटी क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय बैतूल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन में प्रयुक्त पोकलेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिहरित करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल द्वारा प्रस्तुत मामले में बताया कि 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:30 बजे थाना कोतवाली बैतूल पुलिस को मौजा सोनाघाटी स्थित खसरा नंबर 105/5 पर अवैध मुरूम उत्खनन की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां एक चेन माउंटेड पोकलेन मशीन से मुरूम उत्खनन करते हुए पाया गया। पुलिस जब मशीन को थाना ले जा रही थी, उसी दौरान दो खाली डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 5560 एवं एमएच 27 एक्स 0801 उत्खनन स्थल की ओर जाते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों वाहन चालक डम्पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों डम्परों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया। अगले दिन सहायक खनि अधिकारी बैतूल एवं विभागीय अमले द्वारा स्थल निरीक्षण कर गड्ढों की नपाई की गई, जिसमें कुल 3465 घनमीटर मुरूम उत्खनन होना पाया गया। जांच के दौरान पोकलेन ऑपरेटर अज्जू फरकाड़े ने अपने बयान में बताया कि मशीन शेख निजाम निवासी टिकारी की है और उनके कहने पर रात में मुरूम निकालकर डम्परों से परिवहन किया जाता था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अनावेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है। हालांकि दोनों डम्परों को खाली अवस्था में जब्त किए जाने के कारण अवैध परिवहन में उनकी संलिप्तता प्रमाणित नहीं मानी गई। अपर कलेक्टर वंदना जाट ने आदेश पारित करते हुए मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के तहत शेख निजाम पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की। साथ ही जप्तशुदा पोकलेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिहरित करते हुए उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल को मशीन का पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने तथा शास्ति राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत युवक-युवतियों को दिया जा रहा है 45 दिवसीय प्रशिक्षण

रायसेन (निप्र)। राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवक-युवतियों को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जिले के 87 बालक एवं 49 बालिकाओं को माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ हो गया है। प्रशिक्षण स्थल शासकीय कन्या शिक्षा परिसर के सभागार में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय ने सभी प्रतिभागियों को अनुशासन, नैतिक मूल्य, ईमानदारी की महत्ता बताते हुए प्रशिक्षण के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पूर्ण उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त कर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। सभी प्रतिभागियों को स्टेशनरी किट भी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रभारी सहायक संचालक श्री नवीन गुप्ता, माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य श्री सुधीर जैन, अधीक्षिका श्रीमती लक्ष्मी परिहार, अधीक्षक श्री हरिप्रसाद सोनी तथा श्री चन्द्रशेखर यादव उपस्थित रहे।

रायसेन में जनऔषधि केंद्र पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायसेन (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार मेरा युवा भारत रायसेन द्वारा जिले में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत संचालित जन औषधि केंद्र पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को जन औषधि केंद्र की कार्यप्रणाली, उपयोगिता एवं समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने जन औषधि केंद्र का भ्रमण कर वहां संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिला अस्पताल प्रांगण मे। जन औषधि केंद्र के संचालक श्री सुनील प्रजापति द्वारा बताया गया कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां अत्यंत कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में बड़ी राहत मिलती है। प्रतिभागियों को दवाइयों के भंडारण, वितरण, बिलिंग प्रक्रिया, चिकित्सकीय पर्चों के अनुसार दवा उपलब्ध कराने तथा मरीजों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध जेनेरिक दवाइयां गुणवत्ता के मानकों पर पूरी तरह खरी उतरती हैं तथा ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का उद्देश्य देशभर में सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक सम्पन्न

आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण: कलेक्टर विश्वकर्मा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, समय सीमा वाले पत्रों, विभागीय योजनाओं तथा अभियानों की साप्ताहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने बैठक के प्रारंभ में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कार्य की भी समीक्षा करते हुए तहसीलदारों को प्राथमिकता से शेष कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की भी नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की विभागवार समीक्षा के दौरान जिला खाद्य अधिकारी को गंभीरतापूर्वक सीएम हेल्पलाईन निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार शहरी विकास, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयावधि में संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नॉन अटेन्डेन्ट सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए गंभीरता के साथ निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समयावधि में कराएं निराकरण बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि आवेदनों का समयसीमा में निराकरण नहीं हो रहा है। अधिकारी इसे गंभीरता से लें और जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय

सीमा में निराकरण कराएं। साथ ही संबंधित आवेदक को भी निराकरण की कार्यवाही से अवगत कराएं। उन्होंने समाधान ऑनलाईन, सीएम ऑफिस से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की।

इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों और अवमानना प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए समय से जबावदावा दर्ज कराने के लिए कहा। उपज के सुरक्षित भण्डारण और किसानों को शीघ्र राशि भुगतान के निर्देश कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि उपार्जन उपरांत किसानों को राशि भुगतान की कार्यवाही शीघ्रता से की जाए। साथ ही उपार्जित फसल का सुरक्षित भण्डारण भी कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों पर बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि जहां हितग्राहियों को तीसरी किस्त वितरित हो गई है, वहां आवास शीघ्र पूर्ण कराएं। इसी प्रकार समग्र सीडिंग कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि अभी भी 21523 नागरिकों की समग्र सीडिंग होना है, यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने एक बगिया मॉ के नाम परियोजना, धरती आबा अभियान के तहत संचालित कार्य, अटल ग्राम सेवा सदन पंचायत भवनों के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। नागरिकों की स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुचारू रहे। प्रगतिरत नलजल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराएं। साथ ही कहीं से भी पेयजल की समस्या की जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्रता से समाधान कराएं। इसी प्रकार सभी सीएमओ को निर्देशित किया कि पेयजल के संबंध में सभी निकायों को जारी की गई एसओपी का पालन तथा मॉनीटरिंग गंभीरता से कराएं। उन्होंने उपखण्ड वन अधिकारी समिति और ग्राम वन अधिकार समिति के पास लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए। मानसून के दृष्टिगत की जा रहीं तैयारियों की ली जानकारी नगरीय निकायों के कार्यो की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने पीओ डूडा से मानसून के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी निकायों में नालियों की सफाई कराएं, जिससे कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार सभी एसडीएम अपने-अपने अनुभाग में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विगत 10 वर्षो में जिन तालाब या डेम में दुर्घटनाएं हुई हुई हैं, उनकी सूची बनाते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसी प्रकार बारिश में पहुंचविहीन ग्रामों, रपटों, पुल-पुलियों की जानकारी संधारित करने के लिए भी निर्देश दिए। मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में सीएमएचओ को निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर्स तथा जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ तथा अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से टीएल बैठक में उपस्थित रहे।

मप्र वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय नगाइच ने चुनी जवाबदेही

नर्मदापुरम में किया गोदामों का औचक निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय नगाइच ने पदभार ग्रहण करते ही 'सुविधा नहीं, जवाबदेही' का संदेश दिया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपार्जित स्कंध का निजी गोदाम पूर्ण भर जाने की स्थिति में निगम के स्वनिर्मित गोदामों में 120 प्रतिशत तक भंडारण सुनिश्चित किया जाए। इन निर्देशों के धरातल पर क्रियान्वयन की हकीकत परखने के लिए अध्यक्ष श्री नगाइच ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले का आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने शासकीय वेयरहाउस शाखा हथनापुर एवं पॅवारखेडा के भंडारण केन्द्रों का निरीक्षण कर उपार्जन और भंडारण प्रक्रिया की सूक्ष्म जांच की। अध्यक्ष ने संयुक्त भागीदारी योजना के तहत अनुबंधित निजी वेयरहाउस - सांई कृपा वेयरहाउस चौतलाय, बी.जी. वेयरहाउस चौतलाय एवं रघुवीर वेयरहाउस डोलरिया का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निजी गोदामों में अमानक गेहूँ का भंडारण पाए जाने पर उन्होंने समिति प्रबंधक एवं सर्वेयर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि साफ-सुथरा एवं एफएक्यू मापदंड का गेहूँ ही खरीदा जाए। किसी भी स्थिति में अमानक गेहूँ का भंडारण बर्दाश्त नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने वेयरहाउस संचालकों को एप्रोच रोड दुरुस्त करने और श्रमिकों की निर्भरता कम करने के लिए मैकेनाइजेशन अपनाने को प्रेरित किया। साथ ही वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों में दीर्घ अवधि से भंडारित स्कंध के कारण हो रही भंडारण हानि को कम करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशित किया। श्री नगाइच ने सभी शाखा प्रबंधकों को पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जनहित के प्रति सकारात्मक सोच के साथ अनुशासन में रहकर निगम हित में कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक नर्मदापुरम श्री अतुल सोरठे, क्षेत्रीय प्रबंधक भोपाल श्री राजेश अग्रवाल, जिला प्रबंधक मप्रवेलॉका श्री वासुदेव दवण्डे, शाखा प्रबंधक हथनापुर श्री गौरव पटेल, शाखा प्रबंधक बानापुरा श्री शिवराज राजपूत, शाखा प्रबंधक इटारसी श्री नंदकिशोर बेदी एवं शाखा प्रबंधक पॅवारखेडा श्री विनोद बिसारे उपस्थित रहे।

विकासखंड नटेरन की ग्राम पंचायतों में कृषकों के समक्ष पहुंच रहा कृषि रथ

विदिशा (निप्र)। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, कृषि वर्ष 2026 के शुभारंभ के साथ विकासखंड नटेरन के ग्राम रूसल्ली, डांगरवाडा एवं हड़ा में कृषि रथ कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

विदिशा जिले के प्रत्येक विकासखंड अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायतों में कृषि रथ का नियमित भ्रमण किया जाएगा। प्रतिदिन ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि रथ के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन आदि से संबंधित योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकी सुधारों की जानकारी दी जाएगी। विकासखंड तकनीकी प्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा कृषि रथ के माध्यम से जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, फसल विविधीकरण, विभागीय कृषि योजनाओं का प्रचार-प्रसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई-विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था तथा पराली प्रबंधन

जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

डांगरवाडा में किया गया संवाद

आज दिनांक को कृषि रथ ग्राम डांगरवाडा पहुंचा, जहां उपस्थित कृषकों के साथ कृषि विस्तार अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर द्वारा नई ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं पर चर्चा की गई। किसानों ने योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कृषि रथ अभियान के माध्यम से जिले के किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं लाभकारी खेती की दिशा में प्रेरित कर किसान कल्याण वर्ष 2026 को सार्थक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम रूसल्ली एवं हड़ा के कृषकों ने विस्तारपूर्वक जाना कृषि से जुड़े विभागों की योजनाएं

कृषि रथ ग्राम पंचायत रूसल्ली में पहुंचा जहां किसानों द्वारा शासन की कृषिगत योजनाओं को जानने एवं उनसे लाभ प्राप्त कर रहे कृषकों ने अपने विचार साझा किए इसके उपरांत कृषि रथ हड़ा में पहुंचा जहां उद्यानिकी विभाग से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री कुंदन सिंह द्वारा उद्यानिकी विभाग में चल रही प्रक्षेत्र विस्तार संबंधित योजनाओं मुख्यत : फलध्सब्जीध्मसालाध्फूल क्षेत्र विस्तार एवं पीएमएफएमई, जैविक खेती संबंधित योजना के विषय में कृषकों को जानकारी प्रदाय की गई।

केसला में खेल के साथ मनोरंजन, व्यक्तित्व विकास और स्वास्थ्य पर जोर

नर्मदापुरम (निप्र)। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश की आरोह 2026 योजना के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 01 मई 2026 से शुरू हुए ये शिविर तीन अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत जामनी के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में प्रशिक्षक सुमित यादव द्वारा कबड्डी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खेल परिसर में प्रशिक्षक विकास कोरी के नेतृत्व में हॉकी के गुर सिखाए जा रहे हैं, एवं

शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पथरोटा में प्रशिक्षक जगन वारसे द्वारा वालीबॉल एवं एथलेटिक्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण केवल खेल तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत रोजाना योग अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित सात घटकों पर भी काम हो रहा है। इसमें व्यक्तित्व निर्माण, परिवार की सहभागिता और अभिभावकों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष आयोजन शामिल हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है। शिविर को सफल बनाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनजातीय कार्य विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है। आरोह रजिस्ट्रेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को शिविर से जोड़ा जा रहा है।

बाढ़ आपदा पूर्व तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश

विदिशा (निप्र)। प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ एवं राहत कार्यों के संबंध में किए जाने वाले प्रबंधो हेतु तैयारियों संबंधी बैठक में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए अभी से ही सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने विशेष कर बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के दौरान खतरा निर्मित होने की संभावना है उन जगहों का पहले से ही चिन्हांकन कर सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाएं। निर्माण विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी सड़कें व कुल पुलिया डूब क्षेत्र में आती हैं उनका चिन्हांकन कर सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंध सुनिश्चित करें, इसके अलावा सभी तहसीलों में स्थापित वर्षा मापी यंत्रों की जानकारी की प्रतिदिन एंट्री करें व इसकी जानकारी जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में जिले के बांध एवं भराव क्षमता की जानकारी भी दी गई। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने कहा कि उन स्थानों का चिन्हांकन करें जहां नदी किनारे आम नागरिक निवास कर रहे हैं और उन्हें बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के पहले विस्थापित करें। उनके ठहरने के इंतजाम, भोजन-पानी सहित बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं।

प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने बाढ़ बचाव की पूर्व तैयारियों तथा पूर्व प्रबंधो में सुधार, सुझाव पर आधारित कार्यों के क्रियान्वयन को त्वरित संपादन कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिले में बाढ़ आपदा से निपटने पहले से ही अलर्ट हो जाएं, नगर पालिका क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का चिन्हांकन कर लें जिन क्षेत्रों में पूर्व में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी वहां के वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां बाढ़ से निपटने के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरपालिकाओं के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि अभी से ही नगरीय क्षेत्र के वार्डों में नालों और नालियों की साफ सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पानी निकासी होने में समस्या उत्पन्न ना हो और बाढ़ जैसे हालात ना बनें। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने सभी एसडीएमों को भी निर्देश दिए हैं कि खंड स्तर पर भी आपदा पूर्व तैयारी कर बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु अभी से ही इंतजाम कर लें। इसके साथ ही उन्होंने विदिशा जिले के पुल-पुलियों , रिपटा इत्यादि से मिट्टी व अनावश्यक मलबे को हटाए जाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि वर्षा ऋतु में आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान पुल-पुलियों पर यदि पानी हो तो वाहन चालकों को पुल-पुलियों से आवागमन ना करने दिया जाए खासकर यात्री बसों को पुल-पुलियों पर अत्यधिक पानी होने पर निकलने ना दिया जाए इसके लिए बेरीकेट्स लगाकर पुल-पुलियों की निगरानी की जाए ताकि बाढ़ आपदा में कोई जनहानि की घटना घटित ना हो। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में विशेष कर जिले में स्थित जर्जर भवनों का चिन्हांकन कर भवन मालिकों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। उन्हें नोटिस दें या स्वयं अपने स्तर पर ध्वस्त करने के कार्यों का संपादन करें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। इसके अलावा उन्होंने शासकीय भवन जो जर्जर हालत में है विशेष कर स्कूल, आंगनबाड़ी या पशुपालन विभाग के भवन उन्हें यथाशीघ्र शिफ्ट कर लिया जाए। विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशुहानि ना होने पाए।

राइट क्लिक

आखिर इंसानी जान की कीमत आवारा कुत्ते की जान से ज्यादा है....

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में देश में आवारा और खतरनाक कुत्तों को लेकर किसी भी तरह की सहानुभूति और करूणा दिखाने की जगह इंसानी जिंदगी पर मंडराते खतरे को रोकने के लिए पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की इजाज़त दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सम्बन्धित अधिकारी, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों और दूसरे लागू कानूनी प्रोटोकॉल के मुताबिक, कानूनी तौर पर मंजूर उपाय कर सकते हैं, जिनमें उन कुत्तों को मारना भी शामिल है, जो लाइलाज बीमार हैं, पागल या साफ तौर पर खतरनाक और आक्रामक हैं। ताकि इंसानी ज़िंदगी और सुरक्षा पर मंडराते खतरे को असरदार तरीके से खत्म किया जा सके। यही नहीं सर्वोच्च अदालत ने सभी हाई कोर्ट्स को इस मामले की निगरानी के निर्देश दिए हैं, साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश से जहां श्वान पीड़ितों में राहत है, वहीं श्वान प्रेमियों में गहरी निराशा है। ये लोग कुत्तों को इस तरह मारे जाने को 'घटती मानवीय गरिमा' से जोड़कर इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि आवारा कुत्ते के काटे जाने से एक बेगुनाह इंसान के मर जाने की तुलना में खतरनाक कुत्ते को जान से मार देना मानवीय गरिमा को घटाना है। कुत्तों के पक्ष में खड़े ज्यादातर पशु प्रेमी वो हैं, जिनका साबका अपने किसी करीबी की रेबीज से मौत से शायद नहीं पड़ा है।

बेशक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी बहस शुरू हो गई है। लेकिन यह मान लेना कि इंसानी जान की कीमत एक कुत्ते की जान की तुलना में कमतर है, खुद को धोखे में रखने जैसा है। जान चाहे इंसान की हो या फिर चींटी की, जान, जान है, लेकिन वह क्यों और कैसे ली जा रही है या गंवाई जा रही है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

देश में आवारा कुत्तों की संख्या करीब 6 से 7 करोड़ बताई जाती है यानी कि औसत हर 20 भारतीयों के पीछे एक आवारा कुत्ता है तथा इनमें से एक फीसदी भी खतरनाक या पागल होंगे तो इनकी तादाद 6-7 लाख से कम नहीं होगी। इतने कुत्ते कितने लोगों की जान ले सकते हैं, यह सोचें तो भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनमें पालतू कुत्तों की संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि वो सुरक्षा कारणों से, रईसी का दिखावा करने की चाहत में अथवा शुद्ध श्वान प्रेम के कारण पाले जाते हैं। चिंता की बात यह है कि हमारे देश में आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ने, उनकी प्रजनन क्षमता पर अंकुश लगाने तथा किन्हीं कारणों से पागल और हिंसक हो चुके कुत्तों पर नियंत्रण की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर कुत्तों की नसबंदी वगैरह की जाती है, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं है। कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर दूर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है और उनमें से ज्यादातर वापस अपनी गलियों में लौटकर 'शेर' हो जाते हैं। यूं कुत्ता मनुष्य का दोस्त है, लेकिन हिंसक होने पर वह सारे रिश्ते भूल जाता है। भारत में हर साल कुत्ता काटने से करीब 15 से 20 हजार लोगों की मौत होती है। कुत्ता काटने के बाद जो लोग समुचित इलाज के अभाव में रेबीज का शिकार हो जाते हैं, उनकी हालत कुत्तों से भी बदतर हो जाती है। लेकिन श्वान प्रेमी कुत्तों के इस नकारात्मक पहलू को करूणा की दरी के नीचे खिसकाना बेहतर समझते हैं। वैसे यह मामला पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्देश दिया था कि अस्पतालों, बस अड्डों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिकारियों को ऐसे परिसरों से मौजूद आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी करानी होगी। इसके बाद उन्हें डॉग शेल्टर में भेजना होगा। हालांकि तब इस फैसले की व्यावहारिकता पर सवाल उठे थे और कुत्तों के साथ इस तरह के व्यवहार को अमानवीय (या अश्वाननीय) कहा गया था। इसके खिलाफ एनिमल वेलफ़ेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं कोर्ट में दायर हुई थीं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कोर्ट ने अपने पुराने फैसलो को वापस लेने से इंकार कर दिया। कुत्तों के प्रति लाख सहानुभूति के बाद भी कड़वी सच्चाई यही है कि आज आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए मौत का परवाना बन गए हैं।

यद्यपि कोर्ट के इस आदेश पर सख्ती से पालन पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। बावजूद इसके कि कोर्ट ने माना कि आवारा कुत्तों के काटने से लोगों की जान जाने की समस्या बेहद गंभीर रूप ले चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षित व्यवस्था बनाने में नाकाम अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसमें दो राय नहीं कि कुत्तों को भी जीने का और पूरी गरिमा के साथ जीने का हक है। मूक प्राणियों के प्रति संवेदना मानवीय गुण है। लेकिन असल सवाल यह है कि कुत्ता अगर 'श्वान' न रहकर सचमुच 'कुत्ता' हो जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या वह अपनी जान गंवाने का जोखिम उठाता रहे और कुत्तों की जान बख्शता रहे? जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो कुत्तों के मानवाधिकार को मानवीय गरिमा की रक्षा के साथ जोड़कर देख रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस जाले को यह कहकर साफ किया है कि 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमलों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। लिहाजा राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अदालत भी उन कठोर ज़मीनी हक़ीक़तों से आँखें नहीं मूँद सकती, जहाँ बच्चे, विदेशी यात्री और बुजुर्ग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता, जहाँ बच्चों और बुजुर्गों का जीवन केवल शारीरिक ताक़त या क़िस्मत के भरोसे हो।' जाहिर है कि यह फैसला पशु संवेदना के खिलाफ नहीं है। केवल आवारा, हिंसक और पागल हो चुके कुत्तों को लेकर है। आवारा कुत्तों का हर संभव इलाज किया जाए, उन्हें खाना खिलाया जाए, उन्हें आवारा बनने और इंसान पर हमला करने से रोका जाए इत्यादि बातें सैद्धांतिक तौर पर रंजक और आदर्शवादी लगती हैं। लेकिन जरा उन परिवारों के दुख पर भी निगाह डालिए, जिन्होंने आवारा कुत्त के काटे जाने के बाद अपने किसी परिजन को खोया है। इनमें कई तो ऐसे फूल हैं, जो खिलने के पहले ही मुरझा गए और कई ऐसे हैं, जिन्होंने ऐन जवानी अथवा बुढ़ापे में असमय अपने प्राण गवां दिए हैं। और यह कोई पशुप्रेम की राह में दी गई शहादत नहीं है बल्कि आवारा कुत्तों को दी गई विवशताजनित अबाध छूट अथवा कुत्तों को मानव से भी ज्यादा जरूरी प्राणी मान लेने के दुराग्रह का नतीजा है।

प्रदेश में चिंतनीय स्थिति पानी के लिए कुएं में उतर रही महिलाएं

- देवास में पानी के लिए चक्काजाम, खरगोन में पंचायत का घेराव, बड़वानी में गधों से पानी की सप्लाई

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कहीं महिलाएं जान जोखिम में डालकर कुओं में उतर रही हैं तो कहीं लोग सूखी नदी-नालों में झिरियां खोदकर मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। कई गांवों में लोग किलोमीटरों दूर से पानी ला रहे हैं, जबकि कुछ जगह नलों से बदबूदार और कीड़ों वाला पानी सप्लाई हो रहा है।

प्रदेश के कई जिलों में चिंताजनक हालात सामने आए।

खरगोन के टेमला गांव में एक महीने से जल संकट है। 5-6 दिन से नल सूखे हैं और तीन दिन में सिर्फ एक घंटे पानी मिल रहा है। नाराज ग्रामीणों ने चक्काजाम किया।

सीहोर के रामगढ़ समेत कई गांवों में महिलाएं कुओं में उतरकर या सूखी नदियों में झिरियां खोदकर पानी जुटा रही हैं। कई जगह 2 किमी दूर से कपड़े से छानकर पानी लाना पड़ रहा है।

बैतूल के हरिमऊ गांव में नल-जल योजना बंद है और हैंडपंप सूख चुके हैं। करीब एक हजार आबादी 5 किमी दूर गंदे कुएं के भरोसे है। महिलाएं-बच्चे घंटों लाइन में लग रहे हैं।

रायसेन के कोकलपुर गांव में ग्रामीणों ने सरकारी कुएं पर दबंगों के कब्जे का आरोप लगाया है। 2 हजार आबादी को दिनभर में सिर्फ 3-4 कुप्पा पानी मिल रहा है।

मंदसौर के कई इलाकों में डेढ़ महीने से नलों में कीड़े, कचरा और बदबूदार पानी आ रहा है।

सतना के कई गांवों में लोग 2 किमी दूर से पानी लाने को मजबूर हैं।

सांप के काटने से युवक की मौत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कजलीखेड़ा में सांप के काटने से व्यक्ति की 8 दिन चले इलाज के बाद मौत हो गई। बुधवार दोपहर बॉडी का पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अनीस खान पिता मुनीर खान (50) निवासी बोरदा कजलीखेड़ा बिजली विभाग में अटैच कार को ड्राइव करने का काम करते थे। 12 मई को घर के पास खड़े थे। अचानक कुछ चुभने जैसा महसूस हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि जहरीली चीज ने काटा है। तब परिजनों ने घर आकर देखा तो घर की सीढ़ियों के करीब एक छेद में सांप दिखा। जिसके बाद उन्होंने सांप का रेस्क्यू कराया, जिसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया।

द्विशा केस की सीबीआई जांच कराने पत्र लिखेगी सरकार, दोबारा पीएम की मांग खारिज

सीएम बोले- बेल रिजेक्शन आवेदन भी लगाएंगे, पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में द्विशा शर्मा की मौत मामले में मध्यप्रदेश सरकार कोर्ट में बेल रिजेक्शन आवेदन लगाएगी। बुधवार को द्विशा के परिजन ने मंत्रालय में सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम डॉ. यादव ने द्विशा के परिजन को आश्वासन दिया है कि वे सरकार उनकी पूरी मदद के लिए तैयार है। इधर भोपाल कोर्ट ने द्विशा मौत मामले में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर दिया है।

सीएम ने द्विशा के पिता नवनिधि शर्मा को कहा है कि सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखेगी। यदि कोर्ट दोबारा पोस्टमार्टम के संबंध में निर्णय लेता है तो सरकार पार्थिव शरीर को एम्स दिल्ली तक भिजवाएगी। सरकार भोपाल कोर्ट में बेल रिजेक्शन आवेदन लगाएगी।

वहीं द्विशा के परिवार की ओर से भोपाल कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्ट्म के लिए आवेदन दिया था। जिस पर सुनवाई जारी है। कोर्ट से अनुमति मिलती है तो द्विशा का री पोस्टमार्ट्म एम्स दिल्ली में कराया जा सकता है।

गिरीबाला को कंज्यूमर फोरम से हटाने के लिए लिखा पत्र- द्विशा के परिजन ने गिरीबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम के पद से हटाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि गिरीबाला पर दहेज मृत्यु के तहत मामला दर्ज है। इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। गिरीबाला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जज के तौर पर नियुक्त हैं।

समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी- दूसरी ओर पुलिस ने फरार पति समर्थ के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि एसआईटी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पुलिस को सेकंड पोस्टमार्ट्म पर कोई आपत्ति नहीं है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

कौशल प्रशिक्षण से बढ़ रहा बेटियों का आत्मविश्वास

आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रहे कदम

भोपाल (नप्र)। प्रदेश की बेटियां अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएं उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेहतर अवसर दे रही हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ रही हैं। कौशल प्रशिक्षण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

प्रदेश में 934 आईटीआई हैं। इनमें 290 शासकीय और 644 निजी आईटीआई शामिल हैं। इन संस्थानों में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2025 में शासकीय आईटीआई में 94.55 प्रतिशत प्रवेश हुआ। यह अब तक का सर्वाधिक प्रवेश प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शासकीय आईटीआई में 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है।

प्रदेश की आईटीआई में वर्तमान में 71 आधुनिक ट्रेड्स में 15 हजार से अधिक महिला प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), स्टेनोग्राफर हिन्दी और इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेडों में बड़ी संख्या में बेटियाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। यह बदलते माहौल और बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब बेटियां नए क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य को मजबूत बना रही हैं।

महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण देने के लिए प्रदेश में 7 शासकीय महिला आईटीआई संचालित की जा रही हैं। वहीं 56 शासकीय आईटीआई में महिला छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। इनमें

3400 से अधिक सीटें हैं। इससे दूर-दराज क्षेत्रों की बेटियों को भी प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है।

कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का फोकस केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। विभाग महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी लगातार काम कर रहा है। विशेष महिला प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से 777 महिला प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला है। इंदौर स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट द्वारा 509 महिलाओं को निःशुल्क वाहन संचालन प्रशिक्षण दिया गया। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव और मजबूत हुआ है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और निर्धन वर्ग की 13 हजार से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। इससे बड़ी संख्या में बेटियों को प्रशिक्षण जारी रखने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के अंतर्गत हजारों बेटियों को उद्योगों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग का अवसर मिला है। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों में 5660 बेटियाँ शामिल हैं। सागर की सुश्री स्नेहा रजक और रायसेन की सुश्री लिया जैसी युवतियां प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। अब वे अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं।

महिलाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जीवन तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 3000 बेटियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं यूएन वीमेन के सहयोग से बेटियों को स्टेम और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे बेटियाँ एडवांस तकनीक और नए कार्यक्षेत्रों से जुड़ रही हैं।

परम फाउंडेशन के माध्यम से संचालित आईटीआई कौशल कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में बेटियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। धार जिले के सरदारपुर आईटीआई में संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है। इससे बेटियों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी 64 हजार से अधिक बेटियों को कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिला है।

आईईटी हॉस्टल में गांजा पार्टी पकड़ी

- डीएवीवी के सख्त कार्रवाई के संकेत ● तीन छात्र निलंबित, एक का एडमिशन समाप्त करने की तैयारी

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के छात्रावास में सामने आए नशे के मामले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस जांच के एक सप्ताह बाद संस्थान ने चार विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीन विद्यार्थियों को एक सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, जबकि एक विद्यार्थी का प्रवेश समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले मंगलवार को नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आईईटी छात्रावास में छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान चार इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को गांजा सेवन और मादक पदार्थों से जुड़े मामले में पकड़ा गया था। पूछताछ में ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए, जो कथित रूप से छात्रावासों और शिक्षण संस्थानों

तक नशीले पदार्थ पहुंचाने का काम करते थे।

चार छात्र हिरासत में - कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गोल्डन नेस्ट मुंबई निवासी आयुष झा, देवास के राजाराम नगर निवासी विवेक शर्मा, मुरैना के सबलगढ़ निवासी उमंग अग्रवाल और नर्मदापुरम निवासी दीपांशु अहिरवार को हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी आईईटी प्रशासन को भेजी। मामले की गंभीरता को देखते हुए संस्थान की अनुशासन समिति ने चारों विद्यार्थियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की। मामले की रिपोर्ट कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई को सौंपी गई। आईईटी के निदेशक डॉ. प्रतोष बंसल ने बताया कि बीटेक तृतीय वर्ष के एक विद्यार्थी और प्रथम वर्ष के दो विद्यार्थियों को जुलाई से दिसंबर 2026 तक एक सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इस अवधि में वे किसी भी कक्षा, प्रयोगशाला, परीक्षा या संस्थान की अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं एक अन्य विद्यार्थी का प्रवेश समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का संदेश- विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि होस्टल्स में अनुशासन बनाए रखने और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन का भय बना रहे और शिक्षण वातावरण प्रभावित न हो।

एआई की मदद से सिंहस्थ-2028 में होगा सबकुछ

गूगल क्लाउड इंडिया के साथ सीएम मोहन यादव की हुई मीटिंग

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की गूगल क्लाउड इंडिया के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग के दौरान एमपी में स्थापित होने वाले मेगा डेटा सेंटर और सिंहस्थ-2028 को लेकर चर्चा हुई है। सिंहस्थ में एआई की मदद से अच्छी व्यवस्था और प्लानिंग की जाएगी।

इंदौर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना बैठक में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि गूगल क्लाउड इंडिया के साथ राज्य सरकार का एक बड़ा करार होने जा रहा है। सरकार और गूगल क्लाउड के सहयोग से इंदौर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। सेंटर की स्थापना के लिए जल्द ही एमओयू भी साइन किया जाएगा। इस सेंटर से 10 हजार से अधिक एआई डेवेलपर्स को जोड़ा जाएगा, जो मध्यप्रदेश सहित पूरे देश और साउथ ग्लोबल को एआई की रीयल टाइम नीड टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में एआई की मदद

गूगल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बताया कि एआई समिट के दौरान मप्र सरकार से अभूतपूर्व समर्थन और सहयोग मिला। इससे प्रेरित गूगल क्लाउड द्वारा प्रदेश के प्रमुख विभागों कृषि, शिक्षा, वन, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों को एआई से सशक्त किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 आयोजन की तैयारियों में भी एआई सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक संचालन, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को भी अत्याधुनिक एवं तकनीक आधारित बनाया जा सकता है।